आषाढ़ शुक्ल पक्ष -पूर्णिमा, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-10, अंक - 24 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांक: म.प्र./4-474/2024-26

भोपाल
29 जुलाई 2026 बुधवार

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

आज का मौसम
24.6 अधिकतम
22.9 न्यूनतम

भगवा रंग में दौड़ेगी वंदे भारत: सफर के साथ दिखेगी प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत

भोपाल. दोपहर मेट्रो। अब वंदे भारत ट्रेन भगवा रंग में नजर आएगी। रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस को नया आकर्षक स्वरूप दिया गया है। रेलवे के रेल कोच नवीनीकरण कारखाना, झांसी में अत्याधुनिक रोबोटिक पेंटिंग तकनीक से ट्रेन को भगवा रंग में रंगा गया है, जिससे इसकी फिनिशिंग पहले से अधिक आकर्षक और टिकाऊ हो गई है। बाहरी बदलाव के साथ ट्रेन के अंदर भी कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं, ताकि यात्रियों को अधिक आरामदायक और यादगार सफर का अनुभव मिल सके। इस वंदे भारत की सबसे खास विशेषता इसके कोचों का नया आंतरिक स्वरूप है। यात्रियों को सफर के दौरान मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए कोचों में प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की आकर्षक तस्वीरें और कलात्मक प्रतिकृतियां लगाई गई हैं।

राजधानी में साइबर क्राइम के तीन नए मामले, पुलिस ने शुरू की जांच

व्हाट्सएप पर आई फर्जी एपीके फाइल डाउनलोड करते ही हुई लाखों की ठगी

भोपाल। दोपहर मेट्रो

राजधानी में साइबर अपराधियों ने ठगी के नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में सामने आए तीन अलग-अलग मामलों में साइबर ठगों ने फर्जी एपीके फाइल, मोबाइल चोरी के बाद यूपीआई का दुरुपयोग और पार्ट-टाइम नौकरी का लालच देकर कुल 6 लाख 58 हजार 350 रुपये की ठगी कर ली। तीनों मामलों में कमला नगर, जहांगीराबाद और कोटरा सुल्तानाबाद थाना पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सबसे बड़े मामले में कमला नगर निवासी 65 वर्षीय वीरेंद्र शर्मा ने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए इंटरनेट पर मिले नंबर पर संपर्क किया। ठग ने उन्हें व्हाट्सएप पर फर्जी एपीके फाइल भेजी। फाइल डाउनलोड करने के कुछ दिन बाद उनके खाते से 10 ट्रांजेक्शन में 4.35 लाख रुपये निकाल लिए गए। दूसरे मामले में जहांगीराबाद निवासी अधिवक्ता अनिल भार्गव का मोबाइल चोरी होने के बाद साइबर अपराधियों ने यूपीआई के जरिए 37 हजार रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। वहीं, तीसरे मामले में टेलीग्राम पर पार्ट-टाइम नौकरी का झांसा देकर एक युवक और उसकी मां से 1.86 लाख रुपये निवेश के नाम पर ठग लिए गए। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधी लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। इसलिए लोगों को इंटरनेट से मिले नंबरों, अज्ञात फाइलों और ऑनलाइन कमाई के झूठे प्रस्तावों से सतर्क रहने की जरूरत है।

तीन मामलों में ऐसे हुई साइबर ठगी

- डॉक्टर का नंबर इंटरनेट से खोजा, फर्जी एपीके डाउनलोड करते ही खाते से 4.35 लाख रुपये उड़ गए।
- मोबाइल चोरी होने के बाद यूपीआई के जरिए 37 हजार रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए गए।
- पार्ट-टाइम नौकरी और ऑनलाइन रेटिंग का लालच देकर मां-बेटे से 1.86 लाख रुपये निवेश के नाम पर ठग लिए गए।
- तीनों मामलों में कुल 6.58 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी हुई।

साइबर ठगी से बचने के आसान उपाय

- इंटरनेट पर मिले किसी भी मोबाइल नंबर पर तुरंत भरोसा न करें।
- डॉक्टर, अस्पताल या संस्थान का नंबर केवल आधिकारिक स्रोत से लें।
- व्हाट्सएप या एसएमएस पर आई एपीके फाइल या संदिग्ध लिंक डाउनलोड न करें।
- किसी अजनबी के कहने पर स्क्रीन शेयर या रिमोट एक्सेस एप इंस्टॉल न करें।
- बैंक खाते में संदिग्ध लेनदेन दिखते ही तुरंत बैंक को सूचित करें और 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।

एपीके फाइल कैसे बनती है साइबर जाल

एपीके (एंड्रॉयड पैकेज किट) एंड्रॉयड मोबाइल में एप इंस्टॉल करने की फाइल होती है। साइबर ठग व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए फर्जी एपीके फाइल भेजते हैं और उसे डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। जैसे ही उपयोगकर्ता इसे इंस्टॉल करता है, मोबाइल का नियंत्रण अपराधियों तक पहुंच सकता है। इसके बाद वे बैंकिंग एप, ओटीपी, मैसेज, कॉन्टैक्ट और अन्य गोपनीय जानकारी तक पहुंच बनाकर बैंक खाते से रकम निकाल लेते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी अनजान स्रोत से आई एपीके फाइल कभी डाउनलोड न करें।

QR कोड वाली भिक्षावृत्ति का खुलासा

बेटी को इटारसी से भोपाल भेजता था पिता ट्रेन में बैठाकर मंगवाता था डिजिटल भीख

भोपाल। दोपहर मेट्रो

रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का तरीका अब डिजिटल हो गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्यप्रदेश जीआरपी के अभियान ऑपरेशन हमदर्द के दौरान ऐसा मामला सामने आया, जिसने भिक्षावृत्ति के बदलते स्वरूप को उजागर कर दिया। यहां 13-14 साल की एक किशोरी यात्रियों से पैसे मांगने के साथ-साथ क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल भुगतान भी ले रही थी।

जीआरपी की पूछताछ में सामने आया कि किशोरी को उसका पिता इटारसी से अलग-अलग रेलवे रूट पर भेजता था। पिछले करीब एक साल से वह ट्रेनों में सफर कर भोपाल सहित अन्य शहरों में यात्रियों से भीख मांग रही थी। कभी उसे भोपाल आने वाली ट्रेनों में भेजा जाता था तो कभी नागपुर रूट पर।

पिता के मोबाइल से जुड़ा था क्यूआर कोड

जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान के अनुसार, किशोरी के पास मिले क्यूआर कोड की जांच में पता चला कि वह उसके पिता के मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ था। यानी यात्रियों से मिलने वाले छुट्टे पैसों के साथ डिजिटल माध्यम से भी रकम जुटाई जा रही थी। पुलिस के अनुसार, यह

मामला भिक्षावृत्ति के नए डिजिटल तरीके की ओर इशारा करता है।

बाल कल्याण समिति के निर्देश पर कार्रवाई

नाबालिग होने के कारण किशोरी को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए समिति ने पिता के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की। इसके बाद जीआरपी ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-76 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। इस धारा के तहत बच्चे से भिक्षावृत्ति कराने वाले अभिभावक या संरक्षक को पांच वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

बच्चों के नेटवर्क की तलाश में जुटी जीआरपी

पूछताछ में किशोरी यह नहीं बता सकी कि उसके जैसे कितने बच्चे रेलवे स्टेशनों पर भीख मांग रहे हैं। अब जीआरपी इस बात की जांच कर रही है कि कहीं बच्चों को अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर भेजने वाला कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है। इसके लिए जांच टीमों को सक्रिय किया गया है।

ऑपरेशन हमदर्द के तहत कार्रवाई जारी

मध्यप्रदेश जीआरपी का ऑपरेशन हमदर्द एक से 31 जुलाई तक चलाया जा रहा है। अभियान के तहत रेलवे स्टेशनों पर रहने वाले बेसहारा, निराश्रित, महिलाओं और बच्चों की पहचान कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। साथ ही जरूरतमंदों के पुनर्वास और बिछड़े लोगों को परिवार से मिलाने की पहल भी की जा रही है।

त्विषा शर्मा मौत मामले में अब वैज्ञानिक जांच

गिरिबाला सिंह, समर्थ सिंह ने दिए वॉयस सैंपल 11 अगस्त को सीबीआई पेश करेगी चालान

भोपाल। दोपहर मेट्रो

पूर्व मॉडल एवं अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले की जांच में मंगलवार को महत्वपूर्ण प्रगति हुई। न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान आरोपित गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने अपने वॉयस सैंपल सौंप दिए। इससे अब मामले की वैज्ञानिक जांच आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

न्यायालय के आदेश पर दिए गए सैंपल

पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों आरोपितों को दोबारा वॉयस सैंपल देने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को दोनों ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए अपने सैंपल उपलब्ध करा दिए। इन सैंपलों के आधार पर सीबीआई वैज्ञानिक जांच की अगली प्रक्रिया पूरी करेगी।

11 अगस्त को पेश होगा चालान

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को 11 अगस्त तक चालान पेश करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण की अगली सुनवाई भी इसी तारीख को निर्धारित की गई है। अब जांच की आगामी कार्रवाई और चालान में सामने आने वाले तथ्यों पर सभी की नजरें रहेंगी।

बायो मेडिकल वेस्ट नियम-2026 लागू: अस्पतालों और क्लीनिकों पर स्पॉट फाइन के निर्देश

खुले में मेडिकल वेस्ट फेंका तो 4.05 लाख का जुर्माना

भोपाल। दोपहर मेट्रो

राजधानी में मेडिकल वेस्ट के गलत निस्तारण पर अब नगर निगम सख्ती के मूड में है। खुले में बायो मेडिकल वेस्ट फेंकने या उसे सामान्य कचरे में मिलाने वाले अस्पतालों, क्लीनिकों, लैब और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों पर अब मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा। नए बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत ऐसे मामलों में प्रति टन 4.05 लाख रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है। इससे पहले इस तरह के मामलों में अधिकतम 20 हजार रुपये तक का जुर्माना

लगाया जा सकता था। नगर निगम को पिछले कुछ समय से शहर के विभिन्न इलाकों में खुले में मेडिकल वेस्ट मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए निगम ने सभी सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। निगम का कहना है कि मेडिकल वेस्ट का गलत निस्तारण संक्रमण फैलाने के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। नए नियमों के अनुसार मेडिकल वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण का निर्धारित शुल्क 2,700 रुपये प्रति टन है। यदि कोई स्वास्थ्य संस्थान मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकता है या सामान्य कचरे में मिलाता है, तो उस पर निर्धारित शुल्क का 150 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके तहत प्रति किलो 405 रुपये और प्रति टन 4.05 लाख रुपये तक की पेनाल्टी वसूली जाएगी। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने कहा कि मेडिकल वेस्ट के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने या सामान्य कचरे में मिलाने वाले अस्पतालों, क्लीनिकों और लैब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नए नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित हो सके।

मेट्रो एंकर

मुख्यालय की समीक्षा में खुली लापरवाही, अभियोजन पर पड़ सकता है असर

मप्र में दुष्कर्म के 10 से 15 % मामलों में सही धाराएं नहीं लगा रही पुलिस

भोपाल। दोपहर मेट्रो

प्रदेश में दुष्कर्म और पॉक्सो से जुड़े मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं लगाने में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। पुलिस मुख्यालय की समीक्षा में पता चला है कि करीब 10 से 15 प्रतिशत मामलों में या तो आवश्यक धाराएं नहीं लगाई जा रही हैं या फिर ऐसी धाराएं जोड़ दी जाती हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं होती। इससे न्यायिक प्रक्रिया और अभियोजन दोनों प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

पुलिस मुख्यालय ने एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम गठित की है, जो प्रतिदिन दर्ज होने वाले मामलों की समीक्षा कर रही है। जांच में सामने आया कि कई मामलों में पीड़िता की शिकायत के बावजूद मारपीट जैसी धाराएं नहीं जोड़ी

गईं। वहीं पॉक्सो मामलों में पीड़िता की उम्र के अनुसार लगाई जाने वाली विशेष धाराओं का भी सही पालन नहीं किया गया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा) अनिल कुमार ने बताया कि समीक्षा के दौरान मिली कमियों को विवेचना स्तर पर ही सुधारा जा रहा है, ताकि अदालत में अभियोजन कमजोर न पड़े। साथ ही पुलिस अधिकारियों को समय-समय पर पत्र भेजकर सही धाराएं लगाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। 15 जुलाई को भी सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया था।

सबसे अहम बात यह है कि जिन त्रुटियों को अब पुलिस मुख्यालय पकड़ रहा है, वे जिलों में समीक्षा करने वाले अधिकारियों की नजर से पहले ही छूट गई थीं। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने बीएनएस के प्रावधानों के सही क्रियान्वयन पर विशेष निगरानी बढ़ा दी है।

इन महत्वपूर्ण धाराओं की भी हो रही अनदेखी

- मानसिक रूप से दिव्यांग पीड़िता के मामलों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 92(घ) कई बार नहीं जोड़ी गई।
- नाबालिग पीड़िता के गर्भवती होने की स्थिति में पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(जे-2) का समावेश भी कई मामलों में नहीं किया गया।
- पुलिस मुख्यालय ने इन त्रुटियों को गंभीर मानते हुए सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं।
- अधिकारियों का कहना है कि सही धाराएं लगाने से अदालत में अभियोजन मजबूत होगा और दोषियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी।

किन मामलों में मिली सबसे ज्यादा गड़बड़ी?

- 16 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के मामलों में बीएनएस की धारा 65(1) और 12 वर्ष से कम आयु होने पर धारा 65(2) लगाई जानी चाहिए, लेकिन कई मामलों में इनका पालन नहीं हुआ।
- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामलों में केवल धारा 69 लागू होनी चाहिए, लेकिन कई प्रकरणों में इसके साथ दुष्कर्म की सामान्य धारा 64 भी जोड़ दी गई।
- कई मामलों में पीड़िता द्वारा मारपीट की शिकायत के बावजूद संबंधित धाराएं नहीं लगाई गईं।
- इससे आरोपपत्र और न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

जनजातीय संग्रहालय में सजेगा तीजनबाई की लोकगाथाओं का संसार

भोपाल। दोपहर मेट्रो

पंडवानी गायन को देश-दुनिया में नई पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण तीजनबाई की कलात्मक विरासत अब मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में हमेशा के लिए संरक्षित की जाएगी। संस्कृति विभाग ने उनके जीवन, कला और उपलब्धियों से जुड़ी दुर्लभ स्मृतियों को सहेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके योगदान से परिचित हो सकें। महाभारत की कथाओं को अपनी सशक्त आवाज और अद्भुत अभिनय से जन-जन तक पहुंचाने वाली पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजनबाई की कलात्मक विरासत अब मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित की जाएगी।

आषाढ़ शुक्ल पक्ष -पूर्णिमा, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-10, अंक - 24 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांक: म.प्र./4-474/2024-26

भोपाल
29 जुलाई 2026 बुधवार

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

आज का मौसम
24.6 अधिकतम
22.9 न्यूनतम

Page-7

किसानों का रेला... सीएम हाउस जाने पर अड़े, सड़कें जाम

शहर बंधक, प्रशासन लाचार

- नर्मदापुरम रोड के स्कूलों में अवकाश, पुलिस बल की भारी तैनाती
- किसान आंदोलन से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित
- एसएएफ, आरएएफ समेत 20 से अधिक थानों का पुलिस बल अलर्ट पर

भोपाल, दोपहर मेट्रो

समर्थन मूल्य पर मूंग की सरकारी खरीदी समेत अन्य मांगों को लेकर राजधानी पहुंचे किसानों का आंदोलन आज और तेज होता दिख रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करने पर अड़े हैं। प्रशासन ने उन्हें सावरकर सेतु और नर्मदापुरम रोड क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर रोक रखा है, लेकिन किसान वहीं धरने पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री से सीधे वार्ता की मांग कर रहे हैं।

आंदोलन का सबसे बड़ा असर राजधानी के यातायात पर पड़ा है। नर्मदापुरम रोड, 11 मील, मंडीदीप की ओर जाने वाले मार्ग, सावरकर सेतु, आसपास की लिंक रोड और कई प्रमुख चौराहों पर सुबह से ही लंबा जाम लगा रहा। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, मरीज, यात्रियों और दैनिक आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए, जबकि पुलिस लगातार ट्रैफिक डायवर्ट कर स्थिति संभालने की कोशिश करती रही।

यातायात बाधित होने और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए नर्मदापुरम रोड तथा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों के कई निजी स्कूलों ने बुधवार के लिए अवकाश घोषित कर दिया। अनेक अभिभावकों को सुबह तड़के ही स्कूल प्रबंधन की ओर से छुट्टी का संदेश भेजा गया। कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी दिया है।

सीएम जब तक आश्वासन नहीं देंगे, तब तक वापस नहीं लौटेंगे

किसानों का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री स्वयं आकर उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं देंगे, तब तक वे वापस नहीं लौटेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में मूंग की शत-प्रतिशत MSP पर खरीदी, खाद की पर्याप्त उपलब्धता, खेती के लिए नियमित बिजली और अन्य कृषि संबंधी मुद्दे शामिल हैं। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

सुबह से ही रायसेन, सीहोर, हरदा और नर्मदापुरम सहित कई जिलों से किसानों के भोपाल पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसके चलते दिन में भीड़ और बढ़ने की संभावना जताई गई है। पुलिस ने मुख्यमंत्री निवास और वीआईपी क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है तथा आम लोगों से अनावश्यक रूप से प्रभावित मार्गों पर जाने से बचने की अपील की है।

छाती पर मूंग दलती सरकार

राजधानी की सड़कों पर अन्नदाता... संकट खेत में नहीं, व्यवस्था में

मध्यप्रदेश की खुद को किसान हितैषी बताने वाली सरकार इन दिनों प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों की छाती पर ही मूंग दलती नजर आ रही है। अपनी उपज का उचित मूल्य और सरकारी खरीदी की मांग को लेकर किसान अब खेतों से निकलकर राजधानी की सड़कों पर उतर आए हैं। विडंबना यह है कि जिस राज्य को देश में सबसे अधिक मूंग उत्पादन का गौरव प्राप्त है, वहीं के किसान अपनी फसल का वाजिब दाम पाने के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं। 28 जुलाई की शाम नर्मदापुरम संभाग के सैकड़ों किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और पदयात्रा के माध्यम से भोपाल पहुंचे। पुलिस ने उन्हें राजधानी की सीमा पर रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसान बैरागढ़ और बागसेवनिया क्षेत्र पार करते हुए बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच गए। उन्होंने सड़क पर दरी बिछाकर धरना शुरू कर दिया। इस लेख के लिखे जाने तक सड़क पर यातायात बाधित है और किसानों का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है।

प्रसंगवश

राजेश सिरोठिया

मैं स्वयं घटनास्थल पर मौजूद था। किसानों का कहना था कि वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपनी व्यथा सुनाने आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो दूर, सरकार का कोई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी या प्रशासनिक प्रतिनिधि उनसे संवाद करने तक नहीं पहुंचा। पुलिस के अधिकारी अवश्य तैनात रहे, पर उनका काम केवल व्यवस्था बनाए रखना था। प्रशासन चाहता तो किसानों को किसी सभागार, धर्मशाला या मैदान में ठहराकर बातचीत का रास्ता निकाल सकता था। लेकिन संवाद की ऐसी कोई गंभीर कोशिश दिखाई नहीं दी। लोकतंत्र में असहमति का पहला जवाब बातचीत होती है, बैरिकेड नहीं। आंदोलन में शामिल किसान नेता हरिशंकर कुशवाहा का आरोप है कि किसानों ने सरकार को 27 जुलाई तक का समय दिया था। मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि जब सरकार ने उनकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं समझी, तब राजधानी आकर आंदोलन करना उनकी मजबूरी बन गया।

खाद की किल्लत भी बढ़ा रही चिंता

समस्या केवल मूंग खरीदी तक सीमित नहीं है। खरीफ सीजन के बीच खाद की किल्लत भी किसानों की चिंता बढ़ा रही है। सीधी से आए युवा किसान हेमंत बताते हैं कि यूरिया तो उपलब्ध है, लेकिन डीएपी बाजार से लगभग गायब है। एनपीके खाद, जो कुछ समय पहले लगभग 1,200 रुपये में आसानी से मिल जाती थी, अब लगभग दोगुनी कीमत पर बिक रही है। यदि समय रहते यह संकट दूर नहीं हुआ तो खरीफ के साथ-साथ रबी की तैयारी भी प्रभावित होगी।सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभ का धंधा बनाने और किसान कल्याण के बड़े-बड़े दावे करती है। लेकिन जब वही किसान अपनी मेहनत की उचित कीमत मांगने राजधानी पहुंचते हैं, तो उन्हें संवाद के बजाय उपेक्षा मिलती है। इससे सरकार के दावों और जमीन की हकीकत के बीच की दूरी साफ दिखाई देती है।

क्या है मूंग उत्पादकों की समस्या?

मध्यप्रदेश देश का सबसे बड़ा मूंग उत्पादक राज्य है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष देशभर में 5.23 लाख टन मूंग खरीदी का लक्ष्य तय किया है, जिसमें लगभग 4.54 लाख टन, यानी करीब 87 प्रतिशत हिस्सा अकेले मध्यप्रदेश का है। पहली नजर में यह किसानों के लिए राहत की खबर लगती है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू कहीं अधिक चिंताजनक है। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार कुल उत्पादन का केवल 25 प्रतिशत ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाना है। मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों का आरोप है कि सरकार प्रति एकड़ केवल 1.20 क्विंटल उपज ही खरीद रही है, जबकि वास्तविक उत्पादन पांच से छह क्विंटल प्रति एकड़ तक है। बाकी उपज किसानों को खुले बाजार में बेचनी पड़ रही है, जहां भाव मुश्किल से 5,500 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। यानी हर क्विंटल पर ढाई से तीन हजार रुपये तक का नुकसान।

यही वजह है कि किसान पूछ रहे हैं- जब उत्पादन अच्छा हुआ है और सरकार समर्थन मूल्य घोषित कर चुकी है, तो फिर अधिकांश उपज औने-पौने दामों पर बेचने के लिए उन्हें क्यों मजबूर किया जा रहा है?

केंद्र ने भी आईना दिखाया

स्थिति और भी गंभीर इसलिए लगती है क्योंकि राज्य सरकार ने केंद्र से खरीदी का कोटा बढ़ाने की मांग तो कर दी, लेकिन केंद्र ने उल्टा उसे आईना दिखा दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि पहले राज्य सरकार आवंटित लक्ष्य के अनुसार खरीदी पूरी करे, उसके बाद अतिरिक्त कोटे पर विचार होगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एक जुलाई से शुरू हुई खरीदी के पंद्रह दिन बाद तक मध्यप्रदेश केवल 7,947 टन मूंग ही खरीद पाया था, जो आवंटित लक्ष्य का महज 2.1 प्रतिशत है। जबकि खरीदी की अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित है। यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। यदि सरकार आवंटित कोटे की खरीदी ही समय पर नहीं कर पा रही, तो फिर किसानों के आक्रोश के लिए जिम्मेदार कौन है? यह केवल प्रशासनिक सुस्ती नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं का संकट भी है। सरकार चाहे इसे व्यवस्थागत कठिनाई बताए, लेकिन उपलब्ध तथ्य बताते हैं कि मूंग खरीदी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। यदि ऐसा होता तो राजधानी तक पहुंचे किसानों को घंटों सड़क पर बैठा रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता।

जब अन्नदाता को अपनी फसल का दाम मांगने राजधानी की सड़क पर बैठना पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि संकट खेत में नहीं, व्यवस्था में है।

न्यूज विंडो

पीएफआई से की बजरंग दल की तुलना... खड़गे के खिलाफ वारंट जारी

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पंजाब के संगरूर की अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 19 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला 2023 का है। संगरूर निवासी और बजरंग दल से जुड़े हितेश भारद्वाज की शिकायत पर अदालत ने यह कार्रवाई की है। शिकायत में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से की थी।

मनु श्रीवास्तव सिविल सेवा बोर्ड के सदस्य बने

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनु श्रीवास्तव को सिविल सेवा बोर्ड का सदस्य नामित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्रीवास्तव अब भारतीय प्रशासनिक सेवाअधिकारियों के तबादलों, पदस्थापना और अन्य सेवा संबंधी मामलों पर बोर्ड के साथ मिलकर अपना अभिमत देंगे। सिविल सेवा बोर्ड का गठन भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियम, 1954 के नियम-7 में किए गए संशोधन के आधार पर किया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 28 जनवरी 2014 को इन नियमों में संशोधन कर राज्यों में ऐसे बोर्ड के गठन का प्रावधान किया था, ताकि आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति और तबादलों की प्रक्रिया अधिक संस्थागत और पारदर्शी हो सके।

आज का कार्टून

गीता भवन का भी सीएम करेंगे लोकार्पण

उज्जैन में आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव और सांदीपनि अलंकरण समारोह

प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे

उज्जैन, दोपहर मेट्रो। उज्जैन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गीता भवन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व एवं सम्मान समारोह आयोजन में भाग ले रहे हैं।

इस दौरान वे देवास रोड स्थित 34 करोड़ से बने नए गीता भवन का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही आयोजित राज्य स्तरीय 'गुरु पूर्णिमा महोत्सव' एवं सांदीपनि अलंकरण समारोह में नव चयनित प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 'मिशन बुनियाद' का शुभारंभ भी करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में चयनित 7500 प्राथमिक शिक्षकों में से प्रतीकात्मक स्वरूप 10 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण, माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में लगातार 3 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम देने वाले प्रदेश के 6 स्कूल प्राचार्यों का सम्मान, उज्जैन जिले से विभिन्न श्रेणियों में उपलब्धि प्राप्त करने वाले 2 प्राचार्यों एवं नेशनल मींस कम मेरिट परीक्षा में उज्जैन जिले की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी का सम्मान भी किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के पांच सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापकों का भी सम्मान एवं विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया जाएगा। सीएम आज उज्जैन में वीसी में भाग लेकर संत रविदास मंदिर और फिर संदीपनि मंदिर में दर्शन के लिए भी जायेंगे, कार्यक्रम में 17 जिलों के लगभग एक हजार पात्र प्राथमिक शिक्षक शामिल होंगे।

पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र पोस्ट पर एक्स को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान और बाद में सोशल मीडिया पर पीएम नरेन्द्र मोदी और अन्य संवैधानिक पदों को निशाना बनाकर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) को नोटिस भेजा है।पुलिस ने एक्स से संबंधित पोस्ट और वीडियो को तत्काल हटाने या ब्लॉक करने के साथ ही उसे पोस्ट करने वाले अकाउंट की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। पुलिस का कहना है कि यह सामग्री संवैधानिक पदों को निशाना बनाकर प्रसारित की जा रही है और इसकी जांच की जा रही है।

पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी

राहुल बोले- छात्रों के प्रदर्शन में गुस्सा नफरत नहीं, वे अपनी आवाज उठा रहे थे

नई दिल्ली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक से जुड़े 'पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक, 2026' पर लोकसभा में बोलते हुए कहा कि परेशान होकर ही देश का भविष्य सड़कों पर उतरा। बीजेपी में भी जो लोग हैं, हमारे उन मित्रों को जाकर अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या गलत हुआ। प्रदर्शन में गुस्सा, नफरत नहीं थी। वे केवल अपनी आवाज उठा रहे थे। उन्होंने कहा, 'देश के युवाओं का सम्मान होना चाहिए। युवा खुले दिल, खुले विचार के हैं। देश को उन पर नाज है।

इससे पहले लोकसभा में आज कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया जिसके चलते सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद से बिल पर चर्चा जारी है।

कार्रवाई स्थगित रहने के दौरान विपक्ष ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के सांसद अपने हाथों में दानपेटी लिए हुए थे। उन्होंने राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर भाजपा पर हमला बोला। प्रदर्शन में शामिल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा- जो सरकार दानपेटी की रक्षा नहीं कर सकी, वह युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रख सकती। वहीं संसद परिसर में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी पर दिए अपने बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा- मैंने सिर्फ सच कहा है और अगर सच बोलने की सजा मिलेगी तो सच बोलूंगी।

जन्म - मृत्यु पंजीकरण बिल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल, 2026 लोकसभा में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा संशोधन बिल पेश करेंगे। सदन में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज भी पेश किए जाएंगे। पेपर लीक से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में वोटिंग हो सकती है। इसके बाद बिल राज्यसभा में पेश होगा।

एमपी के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, बालाघाट में तीन इंच से ज्यादा बारिश, नदी-नाले उफान पर

भोपाल, दोपहर मेट्रो। प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में इन जिलों में 4 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांढुर्णा, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर में भारी बारिश का अनुमान है।

मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक के मुताबिक, प्रदेश के ऊपर सक्रिय मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मजबूत मौसम प्रणाली बनी हुई है। यह सिस्टम ओडिशा, दक्षिण झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में भारी बारिश कराएगा।

इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का असर भी दिखने लगा है। ग्वालियर में सुबह झमाझम बारिश से लोगों को कई दिनों की गर्मी और उमस से राहत मिली।

दो दिन के लिए चारधाम यात्रा रोकी

मानसून सबसे एक्टिव फेज में पहुंच गया है। इस वक्त देश के ऊपर दो सिस्टम मौजूद हैं। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया आज ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से होते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके असर को देखते हुए अगले 4-5 दिनों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा और अगले 5-6 दिनों में पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इधर, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से तीर्थयात्रा के रास्ते बंद हो गए। खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी गई है।

ईरान जंग में अब सऊदी अरब की एंट्री

अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थक लड़ाकों पर हमले किए, 10 की मौत

तेहरान/वॉशिंगटन डीसी। ईरान जंग में अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। सऊदी ने अमेरिका के साथ मिलकर मंगलवार रात इराक में ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के लड़ाकों के ठिकानों पर हमले किए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसमें 10 लड़ाकों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं।

अमेरिकी सेना के मुताबिक, इन ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की तैयारी की जा रही थी। हमलों के कुछ घंटे बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ये मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर दागी गई थीं, लेकिन सभी को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया।

पीओके की गुहार, भारत हमारी मदद करे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जनता पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आई है। इस बीच पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स पीओके में विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए बेरहमी से बल प्रयोग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षाबल निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चल रहा हैं। प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही जॉइंट अवामी ऐक्शन कमेटी ने बताया है कि सोमवार और मंगलवार के दौरान 30 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। इस बीच पीओके की जनता ने भारतीय सेना से मदद की गुहार लगाई है।

व्यवस्था में बदलाव चाहिए

किसी लोकतंत्र में जब शिक्षा व्यवस्था संकट में हो, न्यायपालिका पर लोगों की निगाहें टिकी हों और युवाओं का भविष्य अदालतों की दहलीज पर खड़ा दिखाई दे, तब किसी मंत्री का इस्तीफा केवल एक राजनीतिक घटना नहीं रह जाता। वह व्यवस्था के सामने खड़े उन सवालों का प्रतीक बन जाता है, जिनका जवाब केवल पद छोड़ देने से नहीं मिलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने एक बार फिर राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली, न्यायिक जवाबदेही और प्रशासनिक सुधारों पर बहस को तेज कर दिया है। इस्तीफे के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या इससे उन करोड़ों युवाओं का भरोसा लौटेगा, जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं? नीट पेपर लीक प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल दोषियों की गिरफ्तारी या कड़े कानून बना देने से समस्या समाप्त नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि परीक्षा प्रणाली में तदर्थ उपायों के बजाय स्थायी संस्थागत सुधार आवश्यक हैं। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा से लेकर परीक्षा संचालन तक की व्यवस्था तब तक भरोसेमंद नहीं बन सकती, जब तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को मजबूत कानूनी आधार, पर्याप्त स्थायी कर्मचारी और स्पष्ट जवाबदेही नहीं मिलती। आज एनटीए सैकड़ों परीक्षाओं का संचालन कर रही है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी संविदा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर निर्भर हैं। ऐसे में गोपनीयता और जवाबदेही दोनों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। दूसरी ओर, न्यायिक व्यवस्था की अपनी चुनौतियां हैं। फास्ट ट्रैक अदालतों के बावजूद लाखों मामले लंबित हैं। उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पद वर्षों से भरे नहीं जा सके हैं। ऐसे में त्वरित न्याय केवल घोषणा बनकर रह जाता है। न्याय मिलने में देरी अंततः न्याय से वंचित होने की भावना पैदा करती है, और यही भावना युवाओं के भीतर व्यवस्था के प्रति अविश्वास को जन्म देती है। हाल के दिनों में अदालतों की मौखिक टिप्पणियों को संदर्भ से काटकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की प्रवृत्ति भी चिंता का विषय बनी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन उसका दुरुपयोग न्यायिक संस्थाओं की गरिमा और जनविश्वास दोनों को प्रभावित करता है।

साधन पथ प्रदर्शक हैं अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले गुरु, किन्तु साध्य नहीं

डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा
स्तंभकार

सद्गुरु पूजनीय, वंदनीय और पथ प्रदर्शक हैं, वह शिष्य के अज्ञान अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी दीपक जलाने वाला और परमात्म प्राप्ति हेतु साधन का दिग्दर्शन कराने वाला महापुरुष है। वह केवल गुरु ही है, जो अपने शिष्य में पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक दर्शन की क्षमता विकसित करता है, गुरु ही अपने शिष्य को कर्म ज्ञान और भक्ति का यथार्थ दर्शन कराता है, जिसके सहारे शिष्य अध्यात्म के उस शिखर पर पहुंच सकता है, जहां जाने के बाद सांसारिक सुख-समृद्धि और वैभव तुच्छ दिखाई देने लगते हैं किंतु वह साध्य नहीं है और न ही ध्येय हो सकता है। ध्येय है, सर्वव्यापी, निर्विकार, निराकार और नियंता, परब्रह्म परमात्मा।

गुरु का महत्व समझाते हुए अक्सर इन पंक्तियों को भी उद्धृत किया जाता है। संत कबीरदास का यह प्रसिद्ध दोहा गुरु की महिमा का बखान करता है-

'गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पायँ।
बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बतायँ।। '

(गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? ऐसे में गुरु के चरण पहले छूने चाहिए क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक पहुँचने का सही मार्ग और ज्ञान दिया है।)

यह सद्गुरु की महिमा है किंतु इस उक्ति का अभिप्राय ऐसा नहीं लिया जाना चाहिए कि गुरु ने गोविंद का पथ बतलाया है इसलिए उन्हें ही पकड़ कर बस वहीं ठहर जाना चाहिए बल्कि इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए कि हम उस गुरु को पहले वंदन करें जो गोविंद को बताकर परे हट गए कि देख यह सीधा सरल रास्ता गोविंद की ओर ही जा रहा है, तू इसे पकड़ ले। तो हम उस गुरु को प्रथम प्रणिपात करें, जिन्होंने गोविन्द को पा लेने का मार्ग बताया ओर अलग हट गए, कि देख गोविन्द तुझे ऐसे मिलेंगे। सद्गुरु कहता है कि अब मेरी आवश्यकता रह ही नहीं जाती है। मेरे द्वारा जो पथ बताया गया है, उस पथ पर ही चलते चलते चले जाना है। सद्गुरु कहता है कि अब तू चलता चला जा उस पथ पर, जो मैंने तुझे बताया है। वास्तविकताओं में भी पथ का दिग्दर्शन कराने के बाद पथ प्रदर्शक की भूमिका आखिर क्या रह जाती है? सद्गुरु ने हमें जो रास्ता बता दिया उसके अनुसार हम अपनी यात्रा शुरू कर दें, यही उचित है। किंतु यदि हम चले नहीं और उस पथ प्रदर्शक या गुरु के पास रुके रह जाएं तो क्या हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे? उत्तर होगा नहीं।

इन पंक्तियों का सार तत्व यही है कि हमें अपने गुरु ने जो रास्ता बताया है, उस पर चलना शुरू कर दें तो परमात्मा रूपी मंजिल मिलेगी। यही है गुरु पूजा और दक्षिणा भी यही है कि उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए गुरु आज्ञानुसार परमात्मतत्व कीर्तन, जप, ध्यान और स्मरण करते हों। पथ प्रदर्शक सतगुरु के बताए अनुसार साधन के माध्यम से ही साध्य परमात्मा को पाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। सारभूत तत्व यही है कि उस गुरु का बड़ा आभार जो कि गोविन्द का पथ बताकर रास्ते से परे हट गए।

गुरू मनुष्य की अंधकार से प्रकाश की आध्यात्मिक यात्रा का प्रेरक तत्व है। गुरु एक सीढ़ी है, जिसके सहारे ऊपर जाया जा सकता है, किंतु यह मंजिल नहीं है जहां जाकर सब यात्राएं विराम पा लेती है। गुरु तैरना सिखा देता है ताकि दरिया को पार किया जा सके, किंतु यदि कोई व्यक्ति जरूरत के वक्त भी गुरु के उस ज्ञान को अंगीकार नहीं करे तो वह डूबने से आखिर कैसे बचेगा? वस्तुतः गुरु एक सीढ़ी है, सीढ़ी के सहारे ऊपर तो चढ़ा जा सकता है किन्तु उसे ही थामे रखकर वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। आचार्य रजनीश कहते हैं, 'गुरु एक सीढ़ी या निसेनी है, जिसपर चढ़कर ऊपर पहुंच जाओ और उसे गिरा दो किंतु यदि तुम उस निसेनी को थाम कर ही बैठे रह गए तो जिस उद्देश्य के लिए निसेनी पर चढ़ कर ऊपर पहुंचे हो तो उसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे।' यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि निसेनी यदि गिरा दोगे तो फिर नीचे कैसे आओगे? कहा जाना चाहिए कि उस अनंत की यात्रा उच्च सोपान की यात्रा है, उस परम पुरुष तक पहुंचने की यात्रा जो कि अध्यात्म का चरम लक्ष्य है, हमारे ऋषियों-महर्षियों ने वैदिकों में इसका गुणगान किया है और महात्मा पुरुषों ने इसकी बहुभांति विवेचना भी की है। गुरु एक माध्यम है, जिसके द्वारा गोविन्द का ज्ञान होता है इसलिए गुरु ने गोविन्द की प्राप्ति के लिए जो साधन बताए हैं, हम वह साधन करें तो उस परमात्म तत्व की प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। किंतु यदि हम गुरु द्वारा बताए गए साधन नहीं करें और गुरु के नाम का ही जाप करते रहें तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसलिए निसेनी गिरा देने का अर्थ इतना ही है कि गुरु को नहीं पकड़े हुए गुरु ने जो उपदेश दिया है उस पर अमल कर आत्मसात करें। साथ ही उन्होंने जो कुछ कहा है अथवा उनके द्वारा जो साधन बताया गया है, उसे पूरी श्रद्धा से अंगीकार करें।

शास्त्र कहते हैं कि शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं किंतु दीक्षा गुरु केवल एक होना चाहिए, किंतु प्रश्न पैदा होता है कि वह कैसा हो? हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि वह अपने शिष्यों के लिए निरपेक्ष भाव से भावित और ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करने वाला हो, न कि गुरु दक्षिणा के नाम पर धन की अपेक्षा रखने वाला हो। आज देखा जाता है कि ज्यादातर महात्मा अपने अनुयायियों को अपने पंथ से जोड़े रखने ओर स्वयं के प्रति पूज्यता के भाव को बनाए रखने के लिए गुरु की महत्ता को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से बखान करते हुए शिष्यों को बांधे रखते है, ऐसा व्यक्ति संत कहला सकता है किंतु वह सद्गुरु नहीं हो सकता। सद्गुरु तो पथ प्रदर्शक है, शिष्य के अज्ञान अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी दीपक जलाने वाला। ऐसा वह गुरु वंदनीय और प्रथम प्रणाम करने योग्य है, वह ब्रह्म स्वरूप है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

मध्य प्रदेश ने दिखाई राह, अब पूरे देश में लागू हो ऐसी पॉक्सो व्यवस्था

डॉ. मयंक चतुर्वेदी
स्तंभकार

भारत में बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध आज सामाजिक संवेदनशीलता और प्रशासनिक उत्तरदायित्व की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुके हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि देश में प्रत्येक वर्ष पॉक्सो अधिनियम के तहत 60 हजार से अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि औसतन प्रतिदिन लगभग 170 से अधिक बच्चे यौन अपराधों का शिकार बन रहे हैं। इन मामलों में मध्य प्रदेश भी लंबे समय से उन राज्यों में शामिल रहा है, जहां पॉक्सो के प्रकरणों की संख्या अधिक दर्ज होती रही है। यह स्थिति चिंता का विषय अवश्य है, किंतु इससे भी अधिक चिंता इस बात की रही है कि अपराध दर्ज होने के बाद पीड़ित बच्चे और उसका परिवार न्याय की पूरी प्रक्रिया में लगभग अकेले पड़ जाते हैं।

यही वह खाली स्थान है, जिसे भरने का प्रयास मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आज किया गया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा की पहल पर तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और उस पर पुलिस मुख्यालय की त्वरित कार्रवाई सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय तक सीमित न होकर यह संदेश है कि अब न्याय का केंद्र पूरी तरह से पीड़ित बच्चा है, हालांकि वह पहले भी केंद्र में ही रहता आया है, पर इसके बाद भी उसे जो न्याय मिलने में देरी हो रही थी, वह नई व्यवस्था से उससे पूरी तरह से राहत दिखाती है और यही सोच इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय बनाती है। वस्तुतः पॉक्सो मामलों की वास्तविक पीड़ा एफआईआर दर्ज होने के बाद शुरू होती है। अधिकांश परिवारों को यह जानकारी ही नहीं होती कि आगे क्या होगा? पुलिस जांच, मेडिकल परीक्षण, न्यायालय में बयान, बार-बार पूछताछ, सामाजिक बदनामी का भय, स्कूल छोड़ने की नौबत, रिश्तेदारों और पड़ोसियों का दबाव तथा कई मामलों में आरोपित पक्ष की धमकियां बच्चे और परिवार दोनों को मानसिक रूप से तोड़ देती हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और विभिन्न बाल अधिकार संगठनों की रिपोर्टें लगातार यह संकेत देती रही हैं कि बड़ी संख्या में पीड़ित बच्चों को पर्याप्त मनोसामाजिक परामर्श, कानूनी मार्गदर्शन और पुनर्वास सहायता समय पर नहीं मिल पाती। यही कारण है कि अनेक मामलों में परिवार मुकदमे की प्रक्रिया से ही टूटने लगता है। इसका कारण भी यह है कि आज जो देश की अदालतों में भी पॉक्सो के हजारों मामले लंबित हैं। इसका अर्थ है कि अनेक बच्चों को वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बने रहना पड़ता है। इतने लंबे समय तक यदि कोई संस्थागत सहयोग उपलब्ध न हो, तो मानसिक आघात और गहरा हो सकता है। कानून अपराधी को सजा दिला सकता है, लेकिन बच्चे के मन से भय तभी निकलता है, जब पूरी व्यवस्था उसके साथ खड़ी दिखाई दे। वास्तव में मध्य प्रदेश की नई एसओपी इसी दृष्टिकोण को व्यवहार में उतारती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पात्र मामले में 'सपोर्ट पर्सन' की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। यह व्यवस्था पॉक्सो अधिनियम और उसके नियमों में पहले से विद्यमान थी, किंतु उसका समान रूप से पालन नहीं हो पा रहा था। अब पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस आयुक्तों, जिला पुलिस अधीक्षकों और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति को सूचना भेजना अनिवार्य होगा, ताकि समय रहते सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया जा सके। यही वह बिंदु है, जो इस पहल को सामान्य प्रशासनिक आदेश से अलग बनाता है। अपराध के बाद शुरुआती 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इसी समय बच्चे को मनोसामाजिक सहयोग, कानूनी सलाह और संस्थागत संरक्षण मिल जाए, तो वह स्वयं को अकेला महसूस नहीं करता। सपोर्ट पर्सन बच्चे और उसके परिवार को पूरी न्यायिक प्रक्रिया समझाता है, विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करता है, पुनर्वास में सहायता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे की गरिमा और सुरक्षा हर स्तर पर बनी रहे।

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय का यह निर्णय इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि उसने आयोग की एसओपी को सिर्फ सलाह के रूप में नहीं छोड़ा, बल्कि उसे प्रशासनिक दायित्व में बदल दिया। केस डायरी में सूचना भेजने की प्रविष्टि, एसपी कार्यालय स्तर पर निगरानी और समयबद्ध अनुपालन की व्यवस्था पूरी प्रक्रिया को जवाबदेह बनाती है। यही वह संस्थागत अनुशासन है, जिसकी कमी अनेक राज्यों में अभी भी महसूस की जाती रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के अन्य राज्य भी इस मॉडल का गंभीर अध्ययन करें। पॉक्सो अधिनियम पूरे देश में समान रूप से लागू है, इसलिए पीड़ित बच्चे को मिलने वाला संस्थागत सहयोग भी समान होना चाहिए। यह स्थिति उचित नहीं कही जा सकती कि किसी राज्य में बच्चे को तत्काल सहायता मिल जाए और दूसरे राज्य में वही बच्चा पूरी प्रक्रिया अकेले झेले। यदि प्रत्येक राज्य बाल अधिकार आयोग ऐसी एसओपी तैयार करे, पुलिस मुख्यालय 24 घंटे की अनिवार्य सूचना व्यवस्था लागू करे, बाल कल्याण समितियों को सक्रिय भूमिका दी जाए और प्रत्येक पात्र मामले में सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, तो देश में बाल संरक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता में व्यापक परिवर्तन आ सकता है। इससे न्यायालयों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य, गवाही और पुनर्वास की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी।

मध्य प्रदेश ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत की है। यहां आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल और पुलिस मुख्यालय की त्वरित कार्रवाई यह दर्शाती है कि यदि विभिन्न संस्थाएं समन्वित रूप से कार्य करें तो बाल संरक्षण कानूनों का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। यह पहल बताती है कि संवेदनशील शासन सिर्फ कानून बनाने से नहीं बनता, इसके लिए कानून को प्रभावी ढंग से लागू कर स्थापित होना होता है, इसलिए आज आवश्यकता यहां मध्य प्रदेश के इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने की है। वस्तुतः हर वर्ष 60 हजार से अधिक पॉक्सो मामलों वाले देश में यह सुनिश्चित करना समय की मांग है कि कोई भी बच्चा एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वयं को व्यवस्था के बीच असहाय न पाए। यदि मध्य प्रदेश की तरह हर राज्य पुलिस, बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण इकाई और विधिक सेवा प्राधिकरण को एक समन्वित तंत्र में जोड़ दे, तो यह भारतीय बाल संरक्षण व्यवस्था में सबसे बड़ा संरचनात्मक सुधार सिद्ध हो सकता है।

यहां यह भी सभी को गंभीरतापूर्वक समझना होगा कि पॉक्सो पीड़ित बच्चों को न्याय सिर्फ न्यायालय से नहीं मिलता है, इसके लिए संवेदनशील व्यवस्था का होना बेहद आवश्यक है। मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब देश के शेष राज्यों की बारी है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

निशाना

चेहरे उजागर हो गये ..!

दिनेश प्रभात

शेर भी लो! मैमने के.. अब बराबर हो गये
देश के लफ़्फ़ाज बच्चों के जवाहर हो गये
खोल में पहचानना आसान इतना था कहाँ
एक अनशन में, सभी चेहरे उजागर हो गये
राष्ट्र की ख़ातिर हमेशा जो दहाड़े थे कभी
कॉकरोचों के अचानक गॉड फादर हो गये
एक प्याऊ थी हमारे पास सबके ही लिये
शत्रु को पानी पिलाने.. लोग गागर हो गये
देशद्रोही सब अचानक...देवता लगने लगे
वे दरी-से बिछ गये, कुछ लोग चादर हो गये
आंदोलन था कहाँ, बस रील बननी थी कई
नेट देने को कई कम्बख़्त.... 'टावर' हो गये
पूछता हूँ क्यों गये जब उस तरफ प्रतिबंध था
आप-से भोले भला....कैसे दिलावर हो गये
आपसे तो आपके बच्चे सँभल पाये नहीं
दूसरों पर बोलिये.. कैसे निछावर हो गये
ढेर-सा पानी लिये हो, प्यास तो बुझती नहीं
दूर तक फैलाव से ही....आप सागर हो गये
नीट की यह नौकरी तो...दूर की कौड़ी हुई
पाँव तक से दूर अब मेंहदी-महावर हो गये
गालियाँ बककर उचक्के चल पड़े परदेस को
सोचिये, इक भूल से.. कितने निरादर हो गये
द्वार पर आये भिखारी सब चमकने लग गये
यूँ कहो, कुछ लोग झूमर और झालर हो गये।

हेल्थ अपडेट

हर बार डायबिटीज का ही संकेत नहीं होता रात में बार-बार यूरिन होना

रात में एक बार पेशाब के लिए उठना उम्र, पानी पीने की आदत या कुछ दवाओं के कारण सामान्य माना जा सकता है। लेकिन यदि हर रात दो या उससे अधिक बार पेशाब के लिए उठना पड़े और इससे आपकी नींद प्रभावित होने लगे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस स्थिति को मेडिकल साइंस में नोक्टूरिया (Nocturia) कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार नोक्टूरिया अपने आप में बीमारी नहीं है, बल्कि यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का शुरुआती संकेत हो सकता है। लगातार नींद टूटने से थकान, ध्यान में कमी, गिरने का खतरा (विशेषकर बुजुर्गों में) और जीवन की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। क्लीवलैंड क्लीनिक के अनुसार सामान्य रूप से रात के समय शरीर एंटीड्यूरेटिक हार्मोन अधिक मात्रा में बनाता है, जिससे किडनी कम मात्रा में यूरिन बनाती है और नींद के दौरान आपको बार-बार पेशाब जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उम्र बढ़ने, हार्मोनल बदलाव, कुछ बीमारियों या दवाओं के कारण यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा रात में अधिक तरल पदार्थ, कैफीन या शराब का सेवन भी बार-बार पेशाब आने की वजह बन सकता है।

एनसीबीआई के अनुसार यदि बार-बार पेशाब आने के साथ अधिक प्यास लगना, बार-बार भूख लगना और वजन घटना जैसे लक्षण भी हों, तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है। जब ब्लड शुगर बढ़ जाती है, तो शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को यूरिन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे बार-बार पेशाब आता है।

नींद से जुड़ी बीमारी का संकेत: साइंस डायरेक्ट के अनुसार कई लोगों को लगता है कि स्लीप एपनिया केवल खर्राटों की बीमारी है, लेकिन यह नोक्टूरिया से भी जुड़ी हो सकती है। स्लीप एपनिया के दौरान सांस बार-बार रुकती है, जिससे शरीर ऐसे हार्मोन छोड़ता है जो यूरिन बनने की मात्रा बढ़ा सकते हैं। यदि रात में पेशाब के साथ तेज खर्राटे, सांस रुकना या दिनभर नींद आना भी हो, तो स्लीप एपनिया की जांच करानी चाहिए।

AI अपडेट

नौकरी खोने के डर से बाहर निकलें, एक्सपर्ट बोले... AI के लिए खुद को बदलने की जरूरत

आजकल हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा है। कोई कह रहा है कि AI आने वाले समय में इंसानों की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो कोई मानता है कि लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इंडस्ट्री के दो बड़े एक्सपर्ट्स की राय इससे काफी अलग है। उनका कहना है कि AI इंसानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि लोगों के काम करने का तरीका बदलेगा। इसलिए डरने के बजाय नई तकनीक को समझना और नए स्किल सीखना ज्यादा जरूरी है।

पेगा (Pega) के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डॉन शुएरमैन का कहना है कि AI कई काम इंसानों से तेज कर सकता है। वह कोड लिख सकता है, डेटा का विश्लेषण कर सकता है और कई बिजनेस प्रोसेस अपने आप पूरे कर सकता है। लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कोई आइडिया ग्राहकों के लिए सही है या नहीं। उनके मुताबिक सही फैसला लेने की क्षमता, नई सोच और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी खूबियां अभी भी इंसानों की सबसे बड़ी ताकत हैं। शुएरमैन के मुताबिक AI उन कामों को करेगा जो बार बार दोहराए जाते हैं। इससे कर्मचारियों के पास क्रिएटिव, रणनीतिक और ग्राहकों से जुड़े कामों के लिए ज्यादा समय होगा।

पेगा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक विश्वेश्वरैया का कहना है कि इतिहास गवाह है कि हर नई तकनीक ने कुछ पुराने काम जरूर बदले हैं, लेकिन साथ ही नए रोजगार भी पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि आज जिन नौकरियों में लोग काम कर रहे हैं, उनमें से कई 50 साल पहले थीं ही नहीं। इसी तरह आने वाले 50 साल में भी ऐसी कई नई नौकरियां होंगी, जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते।

दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत तेजी से दुनिया के बड़े AI हब के रूप में उभर रहा है। डॉन शुएरमैन ने कहा कि अब कई मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में मौजूद अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से ही नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम चला रही हैं। इससे भारत इंजीनियरिंग, रिसर्च और इनोवेशन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। छात्रों और नौकरी करने वालों को AI से डरने की जरूरत नहीं है।

यूजर्स गाइड

कम्युनिटी सोलर तकनीक से छत पर पैनल लगाए बिना भी पा सकते हैं सोलर बिजली

अपने घर की छत पर एक भी सोलर पैनल लगवाए बगैर भी सौर ऊर्जा से बिजली ली जा सकती है। दरअसल हर किसी के पास सोलर पैनल लगवाने के लिए जरूरी जगह या उतना खर्च करने की क्षमता नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए कम्युनिटी सोलर वो तकनीक है जिसकी मदद से बिना भारी-भरकम खर्चा किए या घर की छत का इस्तेमाल किए सोलर से बिजली मिल सकती है। वे लोग जिनके पास अपनी छत नहीं है या जो किरायेदार हैं, वे इस प्लांट में हिस्सेदारी खरीदकर या सब्सक्रिप्शन लेकर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लांट में बनने वाली बिजली सीधा ग्रिड में जाती है। इसके बाद आपके हिस्से की बिजली का डिस्काउंट आपके घर के बिजली बिल में घटा दिया जाता है।

कम्युनिटी सोलर तकनीक में सबसे पहले पावर प्लांट को ऐसी जगह पर लगाया जाता है, जहां भरपूर धूप आती हो। इसे कोई थर्ड पार्टी कंपनी, लोकल अथॉरिटी या बिजली कंपनी लगाती है। वे लोग जिनके पास जगह नहीं है या जो भारी निवेश नहीं कर सकते वे इस प्लांट का एक हिस्सा खरीदकर हिस्सेदार बन सकते हैं या फिर उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पावर प्लांट में बनने वाली बिजली सीधा पावर ग्रिड में जाती है और आपके घर में बिजली सरकारी मीटर के जरिए ही पहुंचती है। प्लांट में बनने वाली कुल बिजली में से आपके हिस्से के आधार पर आपको सोलर क्रेडिट मिलते हैं। बिजली कंपनी इन क्रेडिट्स के आधार पर आपके महीने के बिजली बिल को घटा देती है। इससे आपका बिजली बिल काफी कम हो जाता है।?

बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में भी कम्युनिटी सोलर सिस्टम उपलब्ध है। दरअसल दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने Virtual Net Metering की नीति को मंज़ूरी दे दी है। इसी नीति के तहत कम्युनिटी सोलर काम करता है। दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी में कम्युनिटी सोलर को खास जगह दी गई है। यहां RWA या लोगों का समूह मिलकर एक कॉमन छत या जगह पर सोलर प्लांट लगा सकता है और उसका क्रेडिट अलग-अलग घरों में बांट सकता है।

राज्यस्तरीय ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यशाला में कार्यकर्ताओं ने साझा किए नवाचार और जमीनी अनुभव

आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे बच्चों के विकास -समुदाय के विश्वास का मजबूत केंद्र

दोपहर, दोपहर मेट्रो

भोपाल। मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को और अधिक प्रभावी, आधुनिक एवं बाल-अनुकूल बनाने की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहल तेज कर दी है। इसी उद्देश्य से संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, भोपाल में राज्यस्तरीय विचार-मंथन (ब्रेनस्टॉर्मिंग) कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के सभी संभागों से चयनित सक्रिय, नवाचारी और समर्पित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त निधि निवेदिता ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर उनके अनुभव, सुझाव, नवाचार और मैदानी स्तर पर सामने आने वाली चुनौतियों को जाना।

आयुक्त निधि निवेदिता ने कहा कि कार्यशाला में शामिल लगभग 90 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उच्च शिक्षित हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश की आंगनवाड़ी व्यवस्था नई ऊर्जा, आधुनिक सोच और दक्ष मानव संसाधन के साथ बदलाव के दौर में प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षित कार्यकर्ताओं के जमीनी अनुभवों से प्राप्त सुझाव भविष्य की नीतियों और सुधारों के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेंगे। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केवल शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, मातृ स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक जागरूकता की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। विकसित बचपन ही विकसित मध्यप्रदेश की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को साकार करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम है।

प्रशिक्षण और डिजिटल संसाधनों में होगा सुधार

आयुक्त ने कहा कि राज्यस्तरीय विचार-मंथन का उद्देश्य केवल चर्चा करना नहीं, बल्कि मैदानी स्तर पर काम करने वाली कार्यकर्ताओं की वास्तविक क्षमताओं, चुनौतियों, प्रशिक्षण आवश्यकताओं और सेवा प्रदायगी से जुड़ी समस्याओं को समझना है। प्राप्त सुझावों के आधार पर भविष्य के क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रशिक्षण मॉड्यूल, डिजिटल संसाधनों और सेवा प्रदायगी प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक बनाया जाएगा। संवाद के दौरान कार्यकर्ताओं ने पोषण पुनर्वास, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, डिजिटल तकनीक, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और कुपोषण उन्मूलन से जुड़े सफल प्रयोग साझा किए। आयुक्त ने इन नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न जिलों में विकसित उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों का संकलन कर उन्हें पूरे प्रदेश में मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा।

देवास से मुरैना तक कार्यकर्ताओं की पहल बनी मिसाल

कार्यशाला में देवास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शर्मीला ठाकुर ने बताया कि नगर पालिका के सभापति ने आंगनवाड़ी केंद्रों को एडॉप्ट कर बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई और किशोरियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी कराया। वहीं श्रीमती शोभा ठाते ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र में सहजन के पौधे लगाए गए हैं, जिनकी फलियों का उपयोग पोषण के लिए किया जा रहा है। इसके बदले समुदाय से पोषण वाटिका के लिए बीज आदि प्राप्त किए जा रहे हैं। मुरैना के नावली-194 आंगनवाड़ी केंद्र पर स्थानीय स्व-सहायता समूहों के सहयोग से बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, टेबल और कुर्सियां उपलब्ध कराई गई हैं। यहां प्रतिदिन लगभग 30 से 35 बच्चों की उपस्थिति रहती है। इन प्रयासों से स्पष्ट है कि जनभागीदारी और स्थानीय नवाचारों के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों और समुदाय के लिए अधिक उपयोगी एवं प्रभावी बनाया जा सकता है।

क्रिस्प-मैनिट के बीच एमओयू

युवाओं को मिलेगा भविष्य की तकनीकों का हुनर

भोपाल। देश में स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य की तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस (क्रिस्प) और मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट), भोपाल के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ है। इस साझेदारी के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, डीकार्बोनाइजेशन और कार्बन न्यूट्रल तकनीकों के क्षेत्र में कौशल विकास, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को गति देने का प्रयास किया जाएगा।

यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के विजन के अनुरूप देश में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। दोनों संस्थानों के सहयोग से युवाओं, उद्योगों और तकनीकी संस्थानों को तेजी से उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुरूप प्रशिक्षित करने पर विशेष जोर रहेगा। एमओयू के तहत क्रिस्प और मैनिट संयुक्त रूप से विद्यार्थियों, फैकल्टी, उद्योग प्रतिनिधियों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे। इसके साथ ही फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, औद्योगिक परामर्श सेवाएं और तकनीकी परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों संस्थान तकनीकी शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में भी सहयोग करेंगे। इसका उद्देश्य प्रयोगशालाओं को आधुनिक तकनीकों और उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की पर्यटन गतिविधियों की समीक्षा

पर्यटन विकास को मिलेगी नई रफ्तार निजी निवेश, होमस्टे को मिलेगा बढ़ावा

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और इसे रोजगार एवं आर्थिक विकास का प्रमुख माध्यम बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार और उनके बेहतर संचालन के लिए पर्यटन विभाग वन एवं संस्कृति विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और वनांचलों में स्थित होमस्टे को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुमति और स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाया जाए। निजी निवेश से जुड़ी परियोजनाओं में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पर्यटन विकास से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

पर्यटन स्थलों के विकास में विभागों के बीच बेहतर तालमेल

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश प्राकृतिक संपदा, वन क्षेत्र, ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों की दृष्टि से देश के प्रमुख पर्यटन राज्यों में शामिल है। प्रदेश में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है। वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देते समय पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में होमस्टे पर्यटन को प्रोत्साहित करने से पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली से जुड़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

बड़े शहरों में विकसित होंगे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी बड़े शहरों में निजी निवेश को प्रोत्साहित कर आधुनिक कन्वेंशन सेंटर विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे केंद्र बनने से प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन, व्यावसायिक आयोजन और अन्य बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इससे पर्यटन के साथ होटल, परिवहन, खान-पान और अन्य सेवा क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा।

धार्मिक पर्यटन और कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आस्था से जुड़े प्रमुख स्थलों तक सुगम आवागमन और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। इसलिए धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा, स्वच्छता, परिवहन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर किया जाए।

---

90 फीसद ई-अटेंडेंस अनिवार्य

ऑनलाइन हाजिरी नहीं तो पुरस्कार नहीं! राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड के कड़े नियम

भोपाल, दोपहर मेट्रो

यदि आप मध्य प्रदेश में शिक्षक हैं और रोज ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाते, तो राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की उम्मीद छोड़ दीजिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने पुरस्कारों के आवेदन के लिए नई शर्तें बनाई हैं। इसमें 90 फीसद ई-अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा पोर्टल-3.0 पर ई-अटेंडेंस अपलोड होना चाहिए। वहीं लगातार पांच वर्षों तक 80 फीसद से अधिक परिणाम देने वाले स्कूलों के उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को ही आवेदन का मौका मिलेगा।

इस बार राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए प्रत्येक जिले से दो शिक्षक यानी 110 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस बार नियमित रूप से कक्षा अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही नामांकन के लिए पात्र होंगे। वहीं राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन या नामांकन की पात्रता के लिए शिक्षक की 10 वर्ष की न्यूनतम शिक्षकीय सेवा होना आवश्यक है। पुरस्कार के लिए शिक्षक 10 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। 31 अगस्त तक चयन सूची जारी कर दी जाएगी, ताकि पांच सितंबर शिक्षक दिवस पर इन्हें पुरस्कृत किया जा सके।

ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसमें सेवानिवृत्त शिक्षक, शैक्षिक प्रशासक, शैक्षिक निरीक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग उपर्युक्त नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जनशिक्षक, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, छात्रावास अधीक्षक आदि पुरस्कार के लिए नामांकन नहीं कर पाएंगे। निजी स्कूलों के शिक्षक भी नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे।

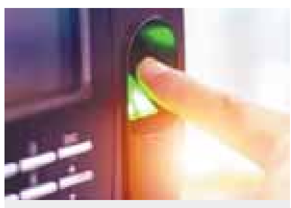

शिक्षक के मूल्यांकन के लिए दो मापदंड होंगे

शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए दो मापदंड ए और बी तय किए गए हैं। इसमें पांच वर्ष के परीक्षा परिणाम के लिए 60 अंक निर्धारित हैं। वहीं 40 अंक शिक्षक द्वारा पांच वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण कार्य, पुस्तक लेखन, विभागीय गतिविधियों में सहभागिता और एफएलएन (स्नरुह) आदि के लिए किए गए कार्य के लिए दिए जाएंगे। इसमें शिक्षक की भाषा-शैली, व्यक्तित्व एवं विषय ज्ञान, शिक्षक का अपने उत्कृष्ट कार्यों पर किया गया प्रस्तुतिकरण और शिक्षकों द्वारा किए गए कार्य का उपलब्धि स्तर पर समग्र प्रभाव पर 10-10 अंक दिए जाएंगे।

सिंधिया राज परिवार संपत्ति विवाद में फिर कानूनी पेंच

बड़ी बुआ की बेटी प्रतिमा देवी राना ने लगाई आपत्ति, अब 17 अगस्त को अगली सुनवाई

ग्वालियर, दोपहर मेट्रो

देश के चर्चित सिंधिया राज परिवार की अरबों की संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपसी सहमति से तैयार हुआ समझौता प्रस्ताव (राजीनामा) एक बार फिर कानूनी अड़चनों में फंस गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय में मंगलवार को इस बहुचर्चित संपत्ति विवाद के समझौते पर सुनवाई हुई। मामले में उस वक्त नया

मोड़ आ गया, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ दिवंगत पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी राना (त्रिपुरा राजघराने से संबंधित) ने इस बंटवारे पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी। प्रतिमा देवी द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति का जवाब देने के लिए ज्योतिरादित्य की बुआ व आपत्तिकर्ता प्रतिमा राजे की तीनों मौसियों (राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, एमपी की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे और उषा राजे) ने न्यायालय से समय मांगा है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त 2026 की तारीख तय की है। इस आपत्ति के बाद समझौते के पुराने प्रस्ताव पर संकट खड़ा हो गया है।

पहले घोषित हुई थीं एक्स पार्टी, अब हक के लिए पहुंचीं कोर्ट

वसुंधरा राजे, उषा राजे और यशोधरा राजे ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा पाने के लिए सिविल सूट दायर किया था। लंबे कानूनी विवाद के बाद हाल ही में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से एक राजीनामा तैयार कर कोर्ट में पेश किया था। मूल दावे में दिवंगत बड़ी बुआ पद्मावती राजे की दोनों बेटियों कनिका देवी सिंह और प्रतिमा देवी राना को पक्षकार तो बनाया गया था, लेकिन पूर्व में सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने के कारण अदालत ने उन्हें एक्स पार्टी (एकपक्षीय) घोषित कर दिया था। अब प्रतिमा देवी ने कोर्ट में आवेदन देकर प्रक्रिया में दोबारा शामिल होने और समझौते में अपना हक पाने की गुहार लगाई है।

कौन हैं प्रतिमा देवी और क्यों उपजा विवाद?- केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे बड़ी बुआ दिवंगत पद्मावती राजे का विवाह त्रिपुरा के राज परिवार में हुआ था। उनकी दो बेटियां प्रतिमा देवी और कनिका देवी हैं। जब सिंधिया राज परिवार के मुख्य सदस्यों के बीच संपत्ति का अंतिम समझौता ड्राफ्ट हुआ, तो उसमें पद्मावती राजे के उत्तराधिकारियों (दोनों बहनों) को शामिल नहीं किया गया।

गायब रिकॉर्ड्स की तलाश, निरस्त हो सकता है राजीनामा

सुनवाई के दौरान एक और बात सामने आई कि मामले की मुख्य फाइल में दावे से जुड़ा पूरा पुराना रिकॉर्ड फिलहाल उपलब्ध नहीं है, जिसकी तलाश अदालत द्वारा की जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि न्यायालय द्वारा प्रतिमा देवी की इस आपत्ति को स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपसी सहमति से तैयार किया गया यह बहुचर्चित राजीनामा पूरी तरह निरस्त हो सकता है और संपत्ति का विवाद नए सिरे से शुरू हो सकता है।

एएआई र्वे पर उठने लगे सवाल

न उड़ान, न यात्री फिर भी देश का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना खजुराहो

खजुराहो । मध्यप्रदेश का खजुराहो एयरपोर्ट एक अनोखी वजह से चर्चा में है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के नवीनतम कस्टमर सैटिस्फैक्शन इंडेक्स में इसे देश का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। हैरानी की बात यह है कि जुलाई और अगस्त के दौरान यहां एक भी कमर्शियल उड़ान संचालित नहीं हो रही है। इस स्थिति ने एविएशन सेक्टर में सर्वे की प्रक्रिया और उसके मानकों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की द्विवार्षिक ग्राहक संतुष्टि सर्वे रिपोर्ट में खजुराहो एयरपोर्ट ने कई व्यस्त और बड़े हवाई अड्डों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि, एक जुलाई से यहां दिल्ली और वाराणसी के लिए संचालित होने वाली दोनों नियमित कमर्शियल उड़ानें बंद हैं। एयरपोर्ट का रनवे इन दिनों पूरी तरह शांत है। खजुराहो एयरपोर्ट के निदेशक संतोष सिंह के अनुसार, फिलहाल दिल्ली और वाराणसी के लिए कोई उड़ान संचालित नहीं हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अक्टूबर से दोनों

मुख्यमंत्री ने दो नई रेल सेवाओं को दिखाई हरी झंडी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन से डॉ. अंबेडकर नगर (महू)-कटरा मालवा एक्सप्रेस सहित दो रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी और बड़ी संख्या में यात्री मौजूद रहे। नई सेवाओं से यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी।

मेट्रो एंकर

20 से ज्यादा बाघों ने अपनाया प्राकृतिक जीवन

मप्र में टाइगर रिवाइल्डिंग मॉडल, अनाथ शावकों को जंगल में बसाया

भोपाल। दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश ने अनाथ और मां से बिछड़े बाघ शावकों को बचाने के साथ उन्हें दोबारा जंगल में बसाने का एक खास रिवाइल्डिंग जंगल में पुन- बसाने% मॉडल विकसित किया है। इस प्रक्रिया में शावकों को केवल सुरक्षित रखने के बजाय प्राकृतिक परिस्थितियों में उन्हें इस तरह तैयार किया जाता है कि वे बड़े होने के बाद बिना इंसानी मदद के शिकार कर सकें और जंगल में स्वतंत्र जीवन जी सकें। प्रदेश में अब तक 20 से ज्यादा बाघ शावकों को प्रशिक्षण देने के बाद प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा चुका है।

प्रदेश के वन बल प्रमुख शुभरंजन सेन के मुताबिक, रिवाइल्डिंग के इस प्रयोग की सफलता यह है कि जिन इलाकों में एक समय बाघों की संख्या लगभग खत्म हो गई थी, वहां दोबारा बाघों की आबादी स्थापित करने में मदद मिली। पन्ना में बाघों की संख्या करीब 100 और नौरादेही में 25 से ज्यादा हो गई है।

पन्ना और नौरादेही ऐसे क्षेत्र रहे हैं, जहां एक समय बाघों की संख्या लगभग शून्य के करीब पहुंच गई थी। यहां अनाथ बाघिनों और शावकों के जोड़ों को उपयुक्त परिस्थितियों में छोड़ा गया। इसके बाद इन क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़ाने में सफलता मिली। इस मॉडल का मकसद केवल बाघों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ना नहीं है। असली लक्ष्य ऐसे बाघ तैयार करना है, जो नए जंगल में खुद शिकार कर सकें, इंसानों से दूरी बनाए रखें और अपना क्षेत्र बना सकें। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर प्रकाश कुमार वर्मा के मुताबिक, अनाथ बाघ शावकों के पुनर्वास के लिए घोरेला क्षेत्र में वर्ष 2006 में विशेष बाड़ा बनाया गया था। यहां शावकों को जंगल जैसा माहौल दिया जाता है। पानी, प्राकृतिक वनस्पति, छिपने की जगह और चीतल जैसे शिकार की व्यवस्था है। घोरेला का अंदरूनी बाड़ा करीब 7 हेक्टेयर में फैला है। इसमें छोटा तालाब, करीब 300 मीटर लंबा नाला, खुले मैदान और साल, आम, महुआ, लेंडिया व तेंदू के पेड़-पौधे हैं।

पहले भोजन, फिर शिकार और आखिर में जंगल

रिवाइल्डिंग की प्रक्रिया में शावक के रेस्क्यू के बाद उसकी स्वास्थ्य स्थिति और उम्र का आकलन किया जाता है। शुरुआत में देखभाल और भोजन दिया जाता है, लेकिन इंसानों से संपर्क न्यूनतम रखा जाता है। इसके बाद प्राकृतिक बाड़े में शावक को छोटे शिकार का अभ्यास कराया जाता है। धीरे-धीरे उसे बड़े शिकार की ओर बढ़ाया जाता है। जब शावक खुद शिकार करने में सक्षम हो जाता है तो उसे चीतल जैसे प्राकृतिक शिकार के साथ बड़े बाड़े में रखा जाता है। अपने दम पर शिकार करना रिवाइल्डिंग की सबसे अहम कसौटी है। शुभरंजन सेन के अनुसार, घोरेला और इस तरह की रिवाइल्डिंग प्रक्रिया से 20 से ज्यादा बाघ शावकों को प्रशिक्षण देकर जंगल में छोड़ा जा चुका है। घोरेला में वर्तमान में करीब 30 माह के दो नर और 19-20 माह की दो मादा बाघों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

तिरंगे में लिपटकर लौटा गांव का लाल: सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी फायर सलामी

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, भारत माता की जय के नारों से गूंजा उदयपुर

गंजबासौदा। दोपहर मेट्रो

ग्राम उदयपुर का वीर सपूत भारतीय सेना का जवान मनीष पाल बीते दिन तिरंगे में लिपटकर अपनी मातृभूमि लौटा तो पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। हर ओर मातम का माहौल था, लेकिन देशभक्ति का जज्बा भी उतना ही बुलंद था। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर फायर सलामी दी, जबकि हजारों लोगों ने भारत माता की जय और मनीष पाल अमर रहें के गगनभेदी नारों के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी। मनीष पाल वर्ष 2018 में भारतीय सेना की 56 आर्मर्ड रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। देश सेवा का सपना लेकर सेना में शामिल हुए इस युवा सैनिक ने कम उम्र में ही अपनी कर्मठता और समर्पण से पहचान बनाई। पिछले लंबे समय से वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और चंडीगढ़ में उनका उपचार चल रहा था। सोमवार को उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। वे मात्र 26 वर्ष के थे। सेना के वाहन से उनका पार्थिव शरीर ग्राम उदयपुर लाया गया। भाल बामोरा चौराहे से पार्थिव यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग तिरंगा हाथों में लेकर शामिल हुए। पूरे मार्ग पर भारत माता की जय के जयघोष गूंजते रहे और श्रद्धालुओं ने पुष्प अर्पित कर अपने वीर सपूत को अंतिम प्रणाम किया। गांव पहुंचने पर सेना के अधिकारियों एवं जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फायर सलामी के बाद पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोग शामिल हुए।

हर आंख नम थी और हर जुबान पर मनीष की देशभक्ति की चर्चा थी। मनीष पाल के जीवन का संघर्ष भी कम मार्मिक नहीं था। उनके पिता दयाराम और बड़े भाई का पहले ही निधन हो चुका था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और देश सेवा का सपना साकार करते हुए भारतीय सेना में भर्ती हुए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने उन्हें असमय हमसे छीन लिया। उनके निधन की सूचना मिलते ही ग्राम उदयपुर विद्यालय का वातावरण भी गमगीन हो गया। विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थी सड़क किनारे कतारबद्ध होकर खड़े हो गए और भारत माता की जय के जयघोष के साथ अपने गांव के वीर जवान को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दृश्य हर किसी की आंखें नम कर गया।

न्यूज विंडो

क्षतिग्रस्त वाहन में मिली अवैध शराब की पेटियां, प्रकरण दर्ज

धार। धरमपुरी तहसील के ग्राम धेगदा रोड पर कल देर रात क्षतिग्रस्त वाहन से अवैध शराब की पेटियों को आबकारी विभाग की टीम ने जब्त किया है। सूचना पर अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची तो लावारिस हालात में सड़क किनारे वाहन क्षतिग्रस्त्र हालत में मिली, तलाशी के दौरान अंग्रेजी शराब व बीयर की पेटियां मिली। आबकारी विभाग की टीम ने वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरु कर दी है। दरअसल प्रतिमाह होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में सहायक आबकारी आयुक्ते दीपक अवस्थी ने जिले के सभी वृत्त अधिकारियों को अवैध शराब परिवहन के खिलाफ ठोस कार्यवाही के निर्देश दिए थे। आबकारी विभाग की टीम कल देर रात जब रात्रि गश्त कर रही थी, इसी एक संदिग्ध वाहन की सूचना अधिकारियों को मिली। सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रशांत मंडलोई के अनुसार ग्राम धेगदा रोड धरमपुरी में एक संदिग्ध बोलेरो चार पहिया वाहन की सघन तलाशी ली गई। वाहन लावारिस हालत में मिलने के कारण उसमें कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं पाया गया, किंतु तलाशी के दौरान वाहन के अंदर से देशी प्लेन मदिरा, ले माउण्ट केन बियर, किंगफिशर केन बियर, लंदन प्राइड एवं मैजिक मूमेन्ट ओरेंज वोदका के पाव बरामद किए गए।

नवनियुक्त एल्डरमैनों का किया स्वागत विकास में भूमिका निभाने का आह्वान

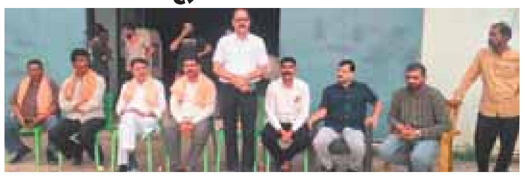

गंजबासौदा। शिवसेना जिला कार्यालय बस स्टैंड बायपास पर युवा जिला अध्यक्ष लोकेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में नगरपालिका के नव नियुक्त सभी छह एल्डरमैनों का शाल, श्रीफल एवं पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष लखन सिंह रघुवंशी एवं शहर मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा का भी नागरिकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त एल्डरमैनों से अपेक्षा जताई कि बे नगर के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगे तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए शहर को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्वागत समारोह में ठाकुर रघुवीर सिंह दांगी, ठाकुर जन्मेद सिंह दांगी, दांगी क्षत्रिय संघ के वरिष्ठ अध्यक्ष भगवत मार साहब, परशुराम कुशवाह, माखन प्रजापति, धर्मेंद्र राजपूत, तारा भावसार, राहुल सक्सेना, पूर्व फौजी हल्कई सिंह दांगी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दांगी क्षत्रिय संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी कमलेश दांगी ने किया, जबकि अंत में वरिष्ठ अध्यक्ष भगवत माड़साब ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त किया। पूरे आयोजन के दौरान उत्साहपूर्ण माहौल रहा और ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच नवनियुक्त एल्डरमैनों का अभिनंदन किया गया।

गुरु पूर्णिमा पर नर्मदा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब

नर्मदापुरम। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताया। संत कबीर का यह प्रसिद्ध दोहा भारतीय संस्कृति में गुरु के सर्वोच्च स्थान को दर्शाता है। गुरु ही मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं और जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। इसी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा और आस्था का पर्व गुरु पूर्णिमा पर नर्मदापुरम में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु सेठानी घाट सहित जिले के विभिन्न घाटों पर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य स्नान किया तथा दान-पुण्य कर परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। स्नान का सिलसिला दोपहर तक चलेगा। स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों एवं अपने-अपने गुरुओं के आश्रमों में पहुंच रहे है, जहां गुरु पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे है। घाटों पर श्रद्धालुओं ने भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण भी किया। मठों, मंदिरों, आश्रमों और गुरुकुलों में विशेष पूजा-अर्चना, सत्संग, भजन-कीर्तन और गुरु वंदना के कार्यक्रम आयोजित किए गए है, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल हो रहे है। गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। सेठानी घाट, कोरी घाट, पर्यटन घाट, परमहंस घाट, विवेकानंद घाट, गोंदरी घाट, बांद्राभान, सांडिया, आंवलीघाट और बाबरी घाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर पुलिस एवं होमगार्ड के जवान तैनात है। श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोका गया, वहीं नावों के माध्यम से लगातार गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी गई।

किसान आंदोलन: भारी पुलिस बल की तैनाती नहीं रोक सकी

औद्योगिक नगर से पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर भोपाल सीमा में पहुंचे किसान

मंडीदीप। दोपहर मेट्रो

किसानों के मुख्यमंत्री निवास घेराव आंदोलन और किसान क्रांति पैदल यात्रा को देखते हुए औद्योगिक नगरी मंडीदीप को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। भोपाल-मंडीदीप सीमा पर कलियासोत ब्रिज के पास सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे। लेकिन किसानों ने पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तोड़ के भोपाल जिले की ओर बढ़ गए।

मंडीदीप, भोपाल और आसपास के थानों से भारी पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। सीमा पर लगभग 100 से अधिक पुलिस जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात किए गए थे। मजबूत बैरिकेडिंग और वज्र वाहन आंदोलनकारियों की हलचल को रोकने के लिए हाईवे के दोनों ओर मजबूत बैरिकेडिंग की गई । साथ ही, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वज्र वाहन भी मौके पर तैनात किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा पुलिस अधीक्षक (एसपी) आशुतोष गुप्ता और एसडीओपी शीला सुराणा ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए मातहत अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान मंडीदीप थाना प्रभारी रंजीत सराठे और नूरगंज थाना प्रभारी संजय यादव अपनी टीमों के साथ मुस्तैद रहे।

किसानों की प्रमुख मांगें और आंदोलन की स्थिति

संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले निकाली जा रही किसान क्रांति पैदल यात्रा बीते दिन भोपाल शहर में पहुंच गई। एक तरफ जहां किसान सड़कों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ जबलपुर हाईकोर्ट ने कृषि आदान विक्रेता संघ की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने प्रदेश में ई-विकास (उर्वरक वितरण) प्रणाली के तहत ऑनलाइन खाद वितरण व्यवस्था को पूरी तरह से सही ठहराया है।

नपा की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

जल प्रदूषण और कचरा अवैध तरीके से किया जा रहा है डंप

कोतमा। दोपहर मेट्रो

नगर पालिका परिषद कोतमा की कार्यप्रणाली को लेकर क्षेत्र में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों एवं पर्यावरण प्रेमियों का आरोप है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा कचरा डंपिंग यार्ड के लिए ग्राम पंचायत चंगेरी की आरजी भूमि, बिजुरी रोड के पास आवंटित किए जाने के बावजूद नगर प्रशासन द्वारा वहां कचरा निस्तारित न कर वार्ड क्रमांक 11 एवं 12 के बीच अवैध रूप से कचरा डंप कराया जा रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि आबादी के समीप कचरा डंप होने से दुर्गंध, मच्छर, मक्खियों एवं अन्य कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे संक्रमण बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। नागरिकों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। एक अन्य आरोप के अनुसार वार्ड क्रमांक 13 स्थित मीरा इंक्लिन के पीछे बने एमआरएफ सेंटर तक पहुंच मार्ग के निर्माण के नाम पर लाखों रुपये के फर्जी बिल तैयार किए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता में नगर से निकलने वाले कचरे को रास्ते में डालकर सड़क तैयार की जा रही है। पर्यावरण प्रेमियों ने यह भी आरोप लगाया है कि नगर का ठोस कचरा, घरों से निकलने वाला अपशिष्ट तथा अन्य संक्रमित एवं जैविक कचरा मीरा खदान के समीप बहने वाले नाले में डाला जा रहा है।

जातिगत प्रताड़ना से तंग आकर सांदीपनी स्कूल के छात्रों का फूटा गुस्सा, पैदल चलकर पहुंचे कलेक्ट्रेट

रसायन शास्त्र शिक्षिका दीपिका शक्तावत पर जातिसूचक शब्दों के प्रयोग और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप

धार। दोपहर मेट्रो

जिले के तिरला स्थित सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आदिवासी छात्र-छात्राओं ने रसायन शास्त्र की शिक्षिका दीपिका शक्तावत पर जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को कक्षा 11वीं और 12वीं के दर्जनों विद्यार्थी करीब 7 किलोमीटर पैदल मार्च कर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त पारुल जैन को ज्ञापन सौंपकर शिक्षिका व लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

छात्रों ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया कि शिक्षिका दीपिका शक्तावत पिछले लगभग एक वर्ष से उनके साथ जातिसूचक और अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षिका उन्हें पढ़ाई-लिखाई और नौकरी के अयोग्य बताते हुए मजदूरी करने तथा गोबर उठाने जैसी बातें कहती हैं। जब छात्र इसका विरोध करते हैं, तो उन्हें डराया-धमकाया जाता है। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने कई बार इस मामले की लिखित शिकायतें कीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 20 जुलाई को अभिभावकों ने भी प्राचार्य सीमा मिश्रा को आवेदन देकर शिक्षिका को हटाने की मांग की थी। छात्रों का कहना है कि प्राचार्य और संबंधित बीईओ न केवल शिकायतों की अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि शिकायत करने वाले छात्रों को ही धमका रहे हैं। इसके कारण विद्यालय में भय का माहौल बना हुआ है।

ज्ञापन में कस्तूरबा/आदिवासी छात्रावास की अव्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें गुणवत्ताहीन भोजन दिया जाता है। शिकायत करने पर छात्रावास से निकालने की धमकी दी जाती है और उनसे झाड़ू-पोछा व बर्तन तक साफ कराए जाते हैं। कलेक्ट्रेट तक 7 किलोमीटर के कड़े पैदल सफर के दौरान अत्यधिक मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण चार छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। आदिवासी छात्र संगठन और विद्यार्थियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शिक्षिका दीपिका शक्तावत, प्राचार्य सीमा मिश्रा और बीईओ के खिलाफ जल्द सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो जिला मुख्यालय पर उग्र और बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

मेट्रो एंकर मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर जालेश्वर महादेव, रतनपुर और भोरमदेव के लिए रवाना होंगे श्रद्धालु

कांवरियों की पावन दस्तक... हर-हर महादेव से गूंजा अमरकंटक

अमरकंटक। दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक तीर्थस्थल तथा मां नर्मदा के उद्गम की पावन नगरी अमरकंटक में श्रावण मास के शुभागमन के साथ ही भक्ति, आस्था और शिवमय वातावरण का अद्भुत संगम दिखाई देने लगा है। बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से संपूर्ण अमरकंटक गूंज उठा है। दूर-दराज से आने वाले कांवरियों की पावन दस्तक के साथ ही नगर में सावन की आध्यात्मिक छटा बिखरने लगी है।

श्रावण मास के अवसर पर मां नर्मदा का पवित्र जल भगवान जालेश्वर महादेव, छत्तीसगढ़ के रतनपुर तथा भोरमदेव महादेव मंदिर में अर्पित करने के लिए बोल बम कांवरियों के दल अमरकंटक पहुंचने लगे हैं। प्रथम दिवस छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के कोदवा ग्राम से लगभग 120 श्रद्धालुओं का कांवरिया दल अमरकंटक पहुंचा। सभी श्रद्धालु अपनी पारंपरिक वेशभूषा में रामघाट, मां नर्मदा उद्गम मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन कर शिवभक्ति में लीन दिखाई दिए। सावन के प्रथम सोमवार की पावन बेला में कांवरिए मां नर्मदा का पवित्र जल कांवर में भरकर भगवान जालेश्वर महादेव के जलाभिषेक के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रद्धालुओं का यह दल अमरकंटक स्थित रामभाई धर्मशाला में ठहरा हुआ है, जहां उनकी सेवा एवं विश्राम की व्यवस्था की गई है।

मां नर्मदा से लिया जल

30 जुलाई से प्रारंभ हो रहे एक माह के पवित्र श्रावण मास में अमरकंटक में देश के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालुओं और कांवरियों के आगमन की संभावना है। इस दौरान मां नर्मदा उद्गम मंदिर, रामघाट, कोटितीर्थ, जालेश्वर महादेव तथा अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा। पूरे नगर में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का अनुपम वातावरण बना रहेगा। श्रावण मास में अमरकंटक की धार्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। मां नर्मदा के उद्गम स्थल से लिया गया पवित्र जल भगवान शिव को अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसी आस्था के साथ प्रत्येक वर्ष हजारों शिवभक्त अमरकंटक पहुंचकर मां नर्मदा का जल अपनी कांवर में भरते हैं और कठिन पैदल यात्रा करते हुए विभिन्न शिवधामों में जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: इतिहास रचने वाले भारत के सितारे

हरजिंदर- गुलवीर ने जीते रजत, बॉक्सिंग में तीन पदक पक्के

ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, पदक तालिका में भारत के 12 मेडल

ग्लासगो, एजेंसी

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। मंगलवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, जब वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किए। वहीं बॉक्सिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई और कम से कम तीन पदक भारत की झोली में पक्के कर दिए। इन उपलब्धियों के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है।

महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में 29 वर्षीय हरजिंदर कौर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीतने वाली हरजिंदर ने इस बार अपने प्रदर्शन को एक नए स्तर पर पहुंचाया। महज 5 फीट 3 इंच लंबी हरजिंदर ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों स्पर्धाओं में दो-दो बार कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने स्नैच में पहले 99 किलोग्राम और फिर 101 किलोग्राम वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में 123 और फिर 126 किलोग्राम वजन उठाते हुए कुल 227 किलोग्राम का भार उठाया। हालांकि कनाडा की चार्लोट सिमोनो ने 240 किलोग्राम कुल वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बावजूद हरजिंदर का यह प्रदर्शन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा और वेटलिफ्टिंग में यह देश का सातवां पदक बना।

गुलवीर सिंह ने रचा नया इतिहास

हरजिंदर की सफलता के कुछ ही मिनट बाद भारतीय एथलेटिक्स को भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि मिली। पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय धावक बन गए। लगातार बारिश और पानी से भरे ट्रैक पर गुलवीर ने बेहतरीन धैर्य और रणनीति का परिचय दिया। शुरुआत से ही वह शीर्ष धावकों के साथ बने रहे और अंतिम लैप में तेज रफ्तार पकड़कर दूसरे स्थान पर फिनिश किया। उन्होंने 27 मिनट 49.78 सेकंड का समय निकाला। ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन ने 27:48.93 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि दोनों के बीच महज 0.85 सेकंड का अंतर रहा।

बॉक्सिंग में तीन पदक हुए पक्के

भारतीय मुक्केबाजों ने भी अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया। एशियाई चैंपियन प्रिया घंघास, एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रीति पवार और जादुमनी सिंह ने अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। बॉक्सिंग में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों का कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित हो जाता है, ऐसे में भारत के तीन और पदक पक्के हो गए हैं। प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम वर्ग में नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड को 5-0 से हराया। वहीं प्रिया घंघास ने 60 किलोग्राम वर्ग में मेजबान खिलाड़ी नियाम मिशेल को 4-1 से मात दी। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमनी सिंह ने जाम्बिया के मवेंगो मवाले को हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। हालांकि भारत को दो मुकाबलों में निराशा भी हाथ लगी। परवीन हुड्डा इंग्लैंड की साचा हिकी से 2-3 के करीबी अंतर से हार गईं, जबकि पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया भी अपना मुकाबला हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए।

पदक तालिका में भारत नौवें स्थान पर

भारत अब तक ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीत चुका है और पदक तालिका में नौवें स्थान पर बना हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 33 स्वर्ण, 17 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 77 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर कायम है। भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में देश के पदकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है।

गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव

भारत को मिला नया फील्डिंग कोच शुभदीप घोष संभाल सकते हैं कमान

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अपने कोचिंग स्टाफ को और मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय टीम के फील्डिंग विभाग में बड़ा बदलाव होने की खबर सामने आई है। बीसीसीआई ने टी. दिलीप का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है और अब उनकी जगह असम के अनुभवी क्रिकेटर एवं कोच शुभदीप घोष को टीम इंडिया का नया फील्डिंग कोच बनाए जाने की संभावना है।

टी. दिलीप ने राहुल द्रविड़ के कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम के फील्डिंग विभाग में कई नई पहल की थीं। ड्रेसिंग रूम में मैच के दौरान सर्वश्रेष्ठ फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी को इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द मैच मेडल देने की परंपरा भी काफी लोकप्रिय हुई थी। हालांकि, पिछले कुछ समय में भारतीय टीम के फील्डिंग प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली है। कैच छोड़ने, स्लिप में गलतियां करने और बाउंड्री पर खराब फील्डिंग जैसी घटनाओं ने टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ाई है।

आयरलैंड और इंग्लैंड के हालिया दौरे के दौरान भारतीय टीम की फील्डिंग में कई खामियां नजर आईं। महत्वपूर्ण मौकों पर कैच छूटने के अलावा स्लिप कॉर्डन में गलतियां और बाउंड्री पर कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे में टीम मैनेजमेंट अब फील्डिंग के तकनीकी पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि शुभदीप घोष का अनुभव भारतीय खिलाड़ियों की फील्डिंग क्षमता को निखारने में मददगार साबित हो सकता है।

कौन हैं शुभदीप घोष?

57 वर्षीय शुभदीप घोष को घरेलू क्रिकेट में जॉय के नाम से जाना जाता है। वह असम के डिगबोई से ताल्लुक रखते हैं। अपने क्रिकेट करियर के दौरान उन्होंने 1994 से 2005 के बीच असम और रेलवे का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 17 प्रथम श्रेणी और 17 लिस्ट-ए मुकाबले खेले। अपने खेल के दिनों में घोष को बेहतरीन और चुस्त फील्डरों में गिना जाता था।

कोचिंग का लंबा अनुभव

शुभदीप घोष के पास कोचिंग का भी लंबा अनुभव है। वह पिछले करीब 15 वर्षों से राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के कोचिंग विभाग से जुड़े रहे हैं। आईपीएल में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स की खिताबी सफलता के दौरान उनके योगदान को अहम माना गया था। इसके अलावा वह दिल्ली कैपिटल्स के फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। ोष भारतीय महिला टीम के 2021 के ऑस्ट्रेलिया दौरे और 2024 अंडर-19 पुरुष विश्व कप के दौरान भी टीम के फील्डिंग कोच रह चुके हैं। उनके अनुभव को देखते हुए माना जा रहा है कि टीम इंडिया के फील्डिंग विभाग को नई दिशा मिल सकती है। गौतम गंभीर के नेतृत्व में भारतीय टीम मैनेजमेंट अब फील्डिंग में निरंतरता और तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। शुभदीप घोष की नियुक्ति होने पर उनका मुख्य लक्ष्य खिलाड़ियों की कैचिंग, स्लिप फील्डिंग, बाउंड्री सेविंग और मैदान पर प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार करना हो सकता है। भारतीय टीम को आने वाले महत्वपूर्ण मुकाबलों में फील्डिंग के मोर्चे पर मजबूत बनाने की दिशा में यह बदलाव अहम साबित हो सकता है।

---

15 साल की अमायरा का विश्व मंच पर धमाका!

इटली में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, स्पीड क्लाइंबिंग में रच दिया नया इतिहास

आर्को, एजेंसी

भारत की 15 वर्षीय स्पीड क्लाइंबिंग प्रतिभा अमायरा खोसला ने इटली के आर्को में आयोजित विश्व युवा क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए नया इतिहास रच दिया। अमायरा ने फाइनल में महज 7.60 सेकंड का समय निकालकर नया भारतीय युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और प्रतियोगिता में छठा स्थान हासिल किया। यह विश्व युवा क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है।अमायरा ने प्रतियोगिता के क्वालीफिकेशन दौर में 7.74 सेकंड का समय निकालकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बेहतर किया था। इसके बाद फाइनल में उन्होंने 7.60 सेकंड का समय लेकर अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया। एक ही विश्व चैंपियनशिप में दो बार व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना उनकी शानदार तैयारी और निरंतर सुधार का प्रमाण माना जा रहा है।

अपनी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए अमायरा ने कहा कि विश्व युवा क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके जीवन के सबसे गर्व के क्षणों में से एक है। उन्होंने कहा कि नया भारतीय युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाना और दुनिया में छठा स्थान हासिल करना किसी सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रदर्शन से उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास मिला है।

भारतीय टीम ने भी छोड़ी अपनी छाप

विश्व युवा क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में भारत की ओर से अमायरा खोसला के अलावा श्लोक दादूकर, नील वार्के और रुद्र करंदीकर ने भी हिस्सा लिया। श्लोक दादूकर ने 6.76 सेकंड के समय के साथ 27वां स्थान प्राप्त किया। नील वार्के ने 7.33 सेकंड का समय लेकर 35वां स्थान हासिल किया, जबकि रुद्र करंदीकर 8.47 सेकंड के साथ 44वें स्थान पर रहे। मुख्य कोच अल्बर्ट ओके ने अमायरा की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत कम समय में असाधारण प्रगति की है। उनके अनुसार, इतनी कम उम्र में विश्व स्तर पर इस तरह का प्रदर्शन उनकी प्रतिभा, अनुशासन और मेहनत का प्रमाण है।

मनोरंजन | **बॉलीवुड का कोना**

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नीतू कपूर ने दिखाई थी बहादुरी दीपक दत्ता ने सुनाया साहस भरा रोचक किस्सा

मुंबई। अभिनेत्री नीतू कपूर का एक ऐसा मानवीय पहलू सामने आया है, जिसने फिल्म जगत में उनकी खूब सराहना बटोरी है। अभिनेता दीपक दत्ता ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान खुलासा किया कि सीमा पर तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पूरी फिल्म यूनिट मुश्किल हालात से गुजर रही थी, तब नीतू कपूर ने अपनी निजी सुरक्षा से पहले पूरी टीम की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। दीपक के मुताबिक, उस कठिन समय में नीतू कपूर ने एक जिम्मेदार कलाकार ही नहीं, बल्कि एक सच्चे नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई।

शूटिंग के दौरान बढ़ गया था सीमा पर तनाव- दीपक दत्ता ने बताया कि फिल्म दादी की शादी की शूटिंग शिमला में चल रही थी। इसी दौरान सीमा पर तनाव बढ़ गया और ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। पंजाब के कई इलाकों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों की

खबरें आने लगीं, जिसके बाद चंडीगढ़ हवाई अड्डे का संचालन भी रोक दिया गया। अचानक बने इस माहौल से पूरी फिल्म यूनिट चिंतित हो गई और सभी कलाकारों व तकनीकी कर्मचारियों के परिवार भी उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान थे।

दिल्ली के रास्ते लौटने की बनी योजना- स्थिति गंभीर होती देख फिल्म यूनिट ने शूटिंग रोकने और सुरक्षित स्थान पर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। चूंकि चंडीगढ़ हवाई अड्डा बंद था, इसलिए सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचने की योजना बनाई गई, जहां से मुंबई के लिए विमान सेवा उपलब्ध थी। पूरी टीम जल्द से जल्द सुरक्षित लौटने के विकल्प तलाश रही थी।

रणबीर कपूर ने भेजना चाहा निजी विमान

दीपक दत्ता ने बताया कि इसी बीच अभिनेता रणबीर कपूर ने अपनी मां नीतू कपूर की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने नीतू कपूर को तुरंत सुरक्षित मुंबई लाने के लिए निजी विमान की व्यवस्था करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन नीतू कपूर ने इस प्रस्ताव को बिना किसी झिझक के अस्वीकार कर दिया। दीपक के अनुसार, नीतू कपूर ने साफ शब्दों में कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। जब पूरी टीम सुरक्षित निकलेगी, तभी मैं भी उनके साथ जाऊंगी। उन्होंने यह भी कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में वे सभी फिलहाल सुरक्षित हैं।

13 साल का दर्द, सालों की चुप्पी... लॉक अप 2 में छलका श्रेया कालरा का सबसे बड़ा राज

मुंबई। रियलिटी शो लॉक अप 2 का नया एपिसोड उस समय बेहद भावुक हो गया, जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर श्रेया कालरा ने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच पहली बार सार्वजनिक किया। शो के टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताना था। इसी दौरान श्रेया ने खुलासा किया कि 13 साल की उम्र में उनके एक कजिन ने उनका यौन शोषण किया था। उनकी आपबीती सुनकर घर का माहौल गमगीन हो गया और कई कंटेस्टेंट्स की आंखें नम हो गईं।

श्रेया ने बताया कि यह घटना तब हुई थी, जब वह अक्सर अपनी नानी के घर जाया करती थीं। उस समय वह केवल 13 साल की थीं और उन्हें यह भी समझ नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक उन्होंने इस दर्द को अपने भीतर ही दबाकर रखा और परिवार के किसी सदस्य को इसके बारे में कभी नहीं बताया। श्रेया ने कहा कि इस घटना की जानकारी केवल उनके बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल को थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह यह राज फिनाले तक पहुंचने के लिए नहीं छिपा रही थीं, बल्कि उन्हें डर था कि सच सामने आने से उनके

परिवार पर गहरा असर पड़ेगा। अपनी बात रखते हुए श्रेया ने कहा कि वह खुद को पीड़ित के रूप में नहीं देखना चाहतीं और न ही लोगों से सहानुभूति की उम्मीद रखती हैं। उनका कहना था कि वह चाहती हैं कि लोग उन्हें उनकी मेहनत और पहचान के आधार पर देखें, न कि उनके अतीत की त्रासदी के कारण। उन्होंने बताया कि जिस रिश्तेदार पर उन्होंने आरोप लगाया, उसकी मां का पहले ही निधन हो चुका था। उनकी अपनी मां ने उस रिश्तेदार की कई वर्षों तक देखभाल की थी।

मेट्रो बाजार

टेस्ला ने भारत में पहला अधिकृत बॉडी शॉप खोला, पुणे में मॉडल वाई की टेस्ट ड्राइव भी शुरू की

नई दिल्ली । इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने मंगलवार को भारत में अपने आफ्टर-सेल्स नेटवर्क का विस्तार करते हुए महाराष्ट्र के पुणे में पहला अधिकृत बॉडी शॉप शुरू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही कंपनी ने शहर में 2026 मॉडल वाई प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव और मॉडल वाईएल की टेस्ट ड्राइव भी शुरू कर दी है।

कंपनी ने बताया कि यह अधिकृत बॉडी शॉप महाराष्ट्र में टेस्ला ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगा। यहां ग्राहकों को ओरिजिनल टेस्ला पार्ट्स, प्रशिक्षित तकनीशियनों और टेस्ला के मानकों के अनुरूप दुर्घटना के बाद मरम्मत और रखरखाव सेवाएं मिलेंगी।

कंपनी के अनुसार, नई सुविधा में पेशेवर दुर्घटना के बाद मरम्मत और बॉडी वर्क, सॉफ्टवेयर आधारित डायग्नोस्टिक्स, असली टेस्ला स्पेयर पार्ट्स और कंपनी द्वारा स्वीकृत मरम्मत प्रक्रियाएं उपलब्ध होंगी। इसका उद्देश्य वाहनों की सुरक्षा और प्रदर्शन को बनाए रखना तथा ग्राहकों के वाहन के मरम्मत में लगने वाले समय को कम करना है।ग्राहकों तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए टेस्ला ने पुणे और आसपास के क्षेत्रों में 2026 मॉडल वाई प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव और मॉडल वाईएल की टेस्ट ड्राइव भी शुरू कर दी है। इच्छुक ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ग्राहक सहायता के माध्यम से टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं।

एक्सपोर्ट ग्रोथ का इंजन बना गुजरात, 863 अरब डॉलर के निर्यात में 110 अरब का योगदान

अहमदाबाद । गुजरात भारत का एक प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक केंद्र ही नहीं है, बल्कि आज देश के एक्सपोर्ट सेक्टर का ग्रोथ इंजन भी बन गया है। दरअसल, भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 863 अरब डॉलर का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है और इसमें 110 अरब डॉलर की हिस्सेदारी के साथ गुजरात सभी राज्यों में नंबर वन है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम उत्पाद, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स ने गुजरात के एक्सपोर्ट को मजबूती प्रदान की है।

बिजनेस जगत से जुड़े लोगों के मुताबिक, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सरकार द्वारा लागू की गई औद्योगिक, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़ी नीतियों की वजह से निर्यात में गुजरात का योगदान लगातार बढ़ रहा है।

राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र पंचानी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ गुजरात ने भी एक्सपोर्ट में अग्रणी भूमिका निभाई है, क्योंकि राज्य की अलग-अलग नीतियां, जैसे गुजरात की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहले नंबर पर रही हैं और हाल ही में जो नई पॉलिसी आई है, वह भारत में आने वाली पहली ऐसी पॉलिसी है।

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार, गुजरात को एक्सपोर्ट सेक्टर में अव्वल बनाने में कम लॉजिस्टिक कॉस्ट और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर की भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के अग्रणी और अत्याधुनिक बंदरगाह गुजरात में है, साथ ही राज्य में कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) भी स्थापित हैं, जो एक्सपोर्ट ग्रोथ के एक बड़े हब के तौर पर उभरे हैं।

चंद्रताल झील: हिमाचल की 'मून लेक' जहां आसमान उतर आता है पानी में

हिमाचल प्रदेश की चंद्रताल झील अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है। 'मून लेक' के नाम से प्रसिद्ध यह झील स्पीति घाटी की सबसे खूबसूरत जगहों में शामिल है। अर्धचंद्राकार आकार में फैली यह झील समुद्र तल से करीब 14 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। झील का साफ और नीला पानी आसपास खड़े ऊंचे पहाड़ों और आसमान की छवि को बेहद मनमोहक बना देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का नजारा किसी चित्रकारी जैसा दिखाई देता है। चंद्रताल झील खासतौर पर ट्रेकिंग, कैंपिंग और रोमांच पसंद करने वाले यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है। शांत वातावरण, बर्फ से ढके पहाड़ और प्राकृतिक सुंदरता इसे हिमाचल के सबसे खास पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं। हालांकि ऊंचाई और कठिन रास्तों के कारण यहां यात्रा करते समय मौसम और स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखना जरूरी होता है।

स्थायी सीटों के विस्तार और वैश्विक दक्षिण को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग

यूएन में भारत का संदेश: सुरक्षा परिषद पर कुछ देशों का दबदबा अब स्वीकार नहीं

यूएन, एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की धीमी रफ्तार को लेकर भारत ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथनेनी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद सुधार की प्रक्रिया कुछ देशों के संकीर्ण और विभाजनकारी हितों की बंधक नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि 17 दौर की बातचीत के बाद भी कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद सुधार से जुड़ी अंतर-सरकारी वार्ता को अगले सत्र तक जारी रखने का फैसला किया है। भारत ने इस निर्णय का समर्थन किया, लेकिन देरी पर चिंता जताते हुए कहा कि अब तय समयसीमा के साथ लिखित मसौदे के आधार पर बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। भारत का कहना है कि वास्तविक सुधार तभी संभव है, जब सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सीटों का विस्तार किया जाए। केवल अस्थायी सीटें बढ़ाने से पांच स्थायी सदस्यों के अधिकारों में कोई बदलाव नहीं आएगा। भारत ने वैश्विक दक्षिण को अधिक प्रतिनिधित्व देने की भी मांग की। इस बीच भारत 2028-29 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के चुनाव की तैयारी कर रहा है। भारत अब तक आठ बार परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है।

पश्चिम एशिया पर भी भारत ने जताई चिंता

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा पर भी चिंता जताई। भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। भारत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होनी चाहिए। पश्चिम एशिया भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते और काम करते हैं। भारत ने गाजा संकट के मानवीय पहलू पर चिंता जताते हुए दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया और सभी पक्षों से बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की।

वहीं, सुरक्षा परिषद सुधार को लेकर कुछ देश स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। इटली, पाकिस्तान, तुर्किये और कनाडा सहित यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस समूह केवल अस्थायी सीटों के विस्तार का समर्थन करता है। यह समूह मानता है कि स्थायी सीटों की संख्या बढ़ाने से शक्ति संतुलन प्रभावित होगा। वहीं भारत सहित कई देश इस सोच का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि दुनिया की बदलती परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षा परिषद की संरचना में बदलाव जरूरी है, ताकि अधिक देशों को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिल सके।

भारत ने किस मुद्दे पर उठाई आवाज

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को फिर मजबूती से उठाया है। राजदूत पार्वथनेनी हरीश ने कहा कि लंबे समय से चल रही सुधार प्रक्रिया अब ठोस नतीजे तक पहुंचनी चाहिए। भारत का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था आज की वैश्विक वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों की सीटों का विस्तार जरूरी है। भारत ने कहा कि केवल अस्थायी सीटें बढ़ाने से निर्णय प्रक्रिया में असली बदलाव नहीं आएगा। नई व्यवस्था में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

लखनऊ कोर्ट में वकीलों पर हाईकोर्ट का शिकंजा

चार अधिवक्ताओं की एंट्री रोकी, बोला- 'काली भेड़ों' पर कड़ी कार्रवाई जरूरी

लखनऊ, एजेंसी

लखनऊ जिला न्यायालय परिसर में वादी और दिल्ली से आए अधिवक्ताओं के साथ मारपीट के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने चार अधिवक्ताओं सौरभ कुमार वर्मा, हर्षित पांडेय, यश पांडेय और अभय प्रताप वर्मा के जिला न्यायालय परिसर में प्रवेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की विशेष पीठ ने कहा कि न्याय वितरण प्रणाली को किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। अदालत ने टिप्पणी की कि अधिकांश अधिवक्ता पूरी ईमानदारी और गरिमा के साथ काम करते हैं, लेकिन वकीलों के बीच मौजूद कुछ 'काली भेड़ों' की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। मामला 21 जुलाई का है, जब दिल्ली की अधिवक्ता अभिप्सा मोहंती, कोमल अग्रवाल और आशुतोष श्रीवास्तव अपने मुवक्किल मोहम्मद शाकिर के संपत्ति विवाद मामले में वकालतनामा दाखिल करने लखनऊ जिला अदालत पहुंचे थे। आरोप है कि वहां कुछ स्थानीय अधिवक्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की और मारपीट की। हाईकोर्ट ने जिला जज की रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद प्रथमदृष्टया चार अधिवक्ताओं की भूमिका पाई। अदालत ने पुलिस और जिला जज को घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने चारों अधिवक्ताओं से पिछले 10 वर्षों के आयकर रिटर्न, संपत्ति, व्यवसाय और पिछले पांच वर्षों में संपत्ति

खरीद-बिक्री का विवरण शपथपत्र के साथ मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

हाईकोर्ट ने क्यों दिखाई सख्ती

हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका को कुछ लोगों के दबाव में नहीं चलने दिया जा सकता। अदालत ने जिला न्यायालय परिसर में हुई घटना को गंभीर मानते हुए कहा कि न्यायिक कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। पीठ ने स्थानीय खुफिया विभाग के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को संबंधित अधिवक्ताओं की गतिविधियों और पृष्ठभूमि की गोपनीय जांच कर सीलबंद रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस आयुक्त और डीजीपी को संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई अधिवक्ता किसी संपत्ति विवाद में पैरवी करने के बाद वही संपत्ति खुद खरीदता है तो यह बार काउंसिल के नियमों का उल्लंघन हो सकता है। अदालत ने इस पहलू पर भी जवाब मांगा है।

दुनिया के 12.2% नाविक भारतीय

समुद्री दुनिया में भारत का दबदबा: नाविकों की सप्लाई में बना दूसरा सबसे बड़ा देश

नई दिल्ली, एजेंसी

समुद्री दुनिया में भारत ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। दुनिया भर में नाविकों की आपूर्ति करने वाले देशों में भारत अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। [illegible] सीफेयरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार, वैश्विक समुद्री कर्मचारियों में भारत की हिस्सेदारी 12.2 प्रतिशत हो गई है।

हर पांच साल में जारी होने वाली यह रिपोर्ट समुद्री क्षेत्र में कर्मचारियों की उपलब्धता और मांग का महत्वपूर्ण आकलन मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में भारतीय नाविकों की वैश्विक हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हुई है, जो देश की बढ़ती समुद्री क्षमता को दर्शाती है। दुनिया में नाविकों की सबसे बड़ी आपूर्ति फिलीपींस करता है, जबकि भारत अब दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। समुद्री क्षेत्र के जानकारों के अनुसार, भारत की सबसे बड़ी ताकत प्रशिक्षित ऑफिसर कैडर में है।

1.4 लाख समुद्री अधिकारी उपलब्ध कराता है भारत

एक अधिकारी के मुताबिक, भारत 1.4 लाख से अधिक समुद्री अधिकारी उपलब्ध कराता है, जो दुनिया के कुल ऑफिसर वर्कफोर्स का करीब 13.4 प्रतिशत है। इसके अलावा भारतीय रेटिंग्स यानी सहायक समुद्री कर्मचारियों की संख्या भी काफी बड़ी है। करीब 1.7 लाख भारतीय रेटिंग्स दुनिया के कुल रेटिंग्स कार्यबल का लगभग 11.29 प्रतिशत हिस्सा हैं। भारत की इस उपलब्धि को वैश्विक समुद्री उद्योग में देश की बढ़ती भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशिक्षित मानव संसाधन, समुद्री शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के कारण भारत आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में और मजबूत स्थिति बना सकता है।

हम युद्ध रोकना चाहते हैं, लेकिन पुतिन नहीं: वोलोदिमिर जेलेंस्की

वाशिंगटन. एजेंसी। अमेरिकी सीनेट में रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को बड़ी बढ़त मिली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसे शांति की दिशा में पहला कदम बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब भी युद्धविराम के लिए तैयार नहीं हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इसके अलावा अमेरिकी सीनेट के दोनों दलों के 60 से अधिक सांसदों से भी बातचीत की। इसी दौरान अमेरिकी सीनेट ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रियात्मक मतदान किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 86 और विरोध में 12 वोट पड़े। जेलेंस्की ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह शांति की दिशा में पहला कदम है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे धंसने के मामले में प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 3 अधिकारी ब्लैकलिस्ट

लखनऊ. एजेंसी। उद्घाटन के 14 दिन बाद ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के कोरारी क्षेत्र में सड़क का हिस्सा धंसने की घटना को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने बड़ी कार्रवाई की है।

एनएचएआइ ने निर्माणकारी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर-सह-डीजीएम (हाइवे) विवेक कुमार गुप्ता, स्वतंत्र इंजीनियर के टीम लीडर सुरेंद्र कुमार

और रेसिडेंट इंजीनियर यतेंद्र कुमार को परियोजना से हटाकर अगले दो वर्षों तक किसी भी परियोजना में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। करीब 4200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ था। उन्नाव के कोरारी क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 64 के पास सड़क का हिस्सा धंसने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। एनएचएआइ की ओर से बताया गया कि बीती 26 जुलाई को रूट पेट्रोलिंग के दौरान सड़क की सतह में स्लिपेज देखा गया। सूचना मिलते ही एनएचएआइ एवं निर्माणकारी संस्था की टीम मौके पर पहुंची और विस्तृत तकनीकी निरीक्षण किया था।

दोपहर मेट्रो

हरिद्वार से 11 लीटर गंगाजल लेकर लौट रहा भक्त, रास्तेभर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

शिवभक्ति... दांतों से कार खींचकर कांवड़ यात्रा पर निकला नरेंद्र

हापुड़, एजेंसी

भगवान शिव के प्रति आस्था और समर्पण का अनोखा उदाहरण इन दिनों देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ के छज्जूपुर गांव निवासी नरेंद्र अपनी अनूठी कांवड़ यात्रा के कारण श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। नरेंद्र हरिद्वार से 11 लीटर गंगाजल और भगवान शिव की प्रतिमा को कार पर रखकर अपने दांतों से कार खींचते हुए अपने गांव की ओर बढ़ रहे हैं।

नरेंद्र ने 10 जुलाई को हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी। इस कठिन यात्रा में उनके साथ गांव के पांच अन्य शिवभक्त और एक 10 वर्षीय बालक भी शामिल हैं। गर्मी से राहत के लिए कार के आगे पंखे की व्यवस्था भी की गई है।

नरेंद्र का कहना है कि यह यात्रा भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा, संकल्प और भक्ति का प्रतीक है। उनका लक्ष्य सावन माह के अंतिम सोमवार तक अपने गांव छज्जूपुर पहुंचना है, जहां

वह प्राचीन महादेव मंदिर में गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।

उनकी अनोखी यात्रा को देखने के लिए रास्ते में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। श्रद्धालु फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ तस्वीरें व वीडियो बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी नरेंद्र की यह कांवड़ यात्रा तेजी से चर्चा में है।

करीब एक महीने तक चलने वाली यह यात्रा भक्ति, धैर्य और समर्पण की अनूठी मिसाल पेश कर रही है।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक **राजेश सिरोठिया** द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रासलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। **संपादक राजेश सिरोठिया**
स्थानीय संपादक अनिल शर्मा* आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) **फोन :** 0755-7963564